नई सोच • नई शुरूआत • नया भारत

अनप्लग इंडिया

सच की आवाज, भारत की पहचान

नोएडा एनसीआर संस्करण

वर्ष : 01 | अंक : 42 | नोएडा, वीरवार, 12 नवम्बर, 2026 | Website: www.unplugindia.com | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 03 रुपए

आज का विचार

‘समय सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ‘



25 बड़े प्रोजेक्ट में देरी, 2 लाख करोड़ खर्च बढ़ा

इतने में 4200 स्कूल बनते 1400 से ज्यादा अस्पताल

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की बड़ी परियोजनाओं में देरी अब सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही है। केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 1,853 चालू परियोजनाओं की लागत 3.22 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित 25 मेगा परियोजनाओं का बजट ही 2.11 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। यह कुल लागत-वृद्धि का करीब 65 फीसदी हिस्सा है। यह राशि इतनी बड़ी है कि इससे 50 करोड़ की लागत वाले 4,200 से अधिक स्कूल या 150 करोड़ रुपए वाले 1,400 से ज्यादा अस्पताल बनाए जा सकते थे। इससे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे दो प्रोजेक्ट भी तैयार हो सकते थे।



कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन 30 साल पीछे- समय-सीमा के मामले में भी स्थिति चिंताजनक है। कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन इसमें सबसे ऊपर है। इसे मार्च 2005 तक पूरा करना था, लेकिन अब इसका लक्ष्य मार्च 2030 कर दिया गया है यानी परियोजना 25 साल पीछे चली गई है। इसके बाद सुबनसिरी और तपोवन-विष्णुगढ़ जैसी जलविद्युत परियोजनाएं हैं, जिनकी समय-सीमा में 16 साल से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब यह है कि जिन सुविधाओं का लाभ जनता को एक-दो दशक पहले ही मिल जाना चाहिए था, उनके लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि, 1,360 परियोजनाएं ऐसी भी हैं, जो समय पर या केवल दो साल तक के विस्तार के साथ चल रही हैं।

सरकार बदलने से प्राथमिकता बदलती है,फंड में देरी होती है- पीडब्ल्यूडी के पूर्व प्रमुख हरिओम शर्मा के मुताबिक, कई बार लंबे प्रोजेक्ट के दौरान सरकार बदलने से जब नई सरकार की प्राथमिकता बदल जाती है तो फंड जारी होने में दिक्कतें भी आती हैं, उससे प्रोजेक्ट और डिले होते हैं।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला

तीन जवान गंभीर रूप से घायल, इलाके की सुरक्षा की गई सख्त

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने सीआरपीएफ के अखरान कैंप में नाका ड्यूटी पर तैनात जवानों पर फायरिंग कर दी। घटना करीब 2.15 बजे की है। इसमें तीन जवान घायल हो गए। उन्हें अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षाबल हमलावरों की तलाश में जुटे हैं। हालांकि किसी आतंकी संगठन ने तत्काल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि यह हमला लश्कर ए तैयबा का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले द रजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ के आतंकी लतीफ बट के माडयूल ने किया है। जानकारी के अनुसार, कुलगाम के आखरन नौपुरा में बुधवार की दोपहर को आतंकियों ने सीआरपीएफ 46वीं वाहिनी के जवानों ने एक नाका लगाया हुआ था। नाका पार्टी वहां से गुजरने



वाले वाहनों व लोगों की जांच पढ़ताल कर रही थी। लगभग सवा दो बजे के करीब मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक नाके पास पहुंचे और उन्होंने नाका पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की।

एक जवान की टांग दूसरे के बाजू और तीसरे की पीठ में लगी गोली

हमले की सूचना मिलते ही निकटवर्ती शिविरों से सुरक्षाबलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने उसी समय पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए घायल जवानों को उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया। जहां उनकी पहचान हैड कांस्टेबल सोमवीर, कांस्टेबल शांतुनु और कास्टेबल राकेश दास के रूप में हुई है। डाक्टरों के अनुसार, एक जवान की टांग में, एक के बाजू में और एक की पीठ में गोली लगी है। इस बीच, सुरक्षाबलों ने घटनास्थल के आस पास के सभी इलाकों में तलाशी अभियान चलाया है। घटनास्थल के आस पास उपलब्ध सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच की जा रही है। सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।

10 महीने में 16 फीसदी गिरा बाजार, महीने भर में रिकवरी

सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर 81,500 पर, निफ्टी में 100 अंक की तेजी

मुंबई (एजेंसी)। शेयर बाजार में सेंसेक्स बुधवार को 400 अंक चढ़कर 81,500 के पार पहुंच गया। यानी, इसमें 0.5 फीसदी की बढ़त है और इससे निवेशकों की दौलत 6 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। इधर, निफ्टी 100 अंक की तेजी के साथ 25,130 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसमें 0.34 फीसदी की तेजी है। आज बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त है।



1 जनवरी 2026 को सेंसेक्स 85,188 के स्तर पर था। इसके बाद बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और 1 अक्टूबर को सेंसेक्स 71,292 के इस साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया। इस दौरान बाजार 16 फीसदी या 13,896 अंक टूटा। 1 अक्टूबर को 71,292 का निचला स्तर छूने के बाद बाजार में तेजी आई। बीते एक महीने में सेंसेक्स 15 फीसदी या 11,228 अंक बढ़कर 82,520 के स्तर पर पहुंच गया है, जिससे पिछले 10 महीनों में हुई गिरावट की लगभग भरपाई हो गई है।

शेयर बाजार में तेजी की तीन बड़ी वजह- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट: अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, जिससे मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई रुकने या प्रभावित होने का डर कम हो गया है। इस खबर के बाद ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें घटकर दो महीने के निचले स्तर यानी 89.16 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं। भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है।

राजस्थान के वीर शासकों की गौरवगाथाओं पर बनेगी फिल्म ‘शासक’

पिक्चर का फर्स्ट लुक जारी, नरेंद्र सिंह मीणा करेंगे निर्देशन

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान की धरती ने इतिहास में ऐसे कई वीर शासकों को जन्म दिया, जिनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम और युद्ध कौशल की गाथाएं आज भी देशभर में गर्व के साथ सुनाई जाती हैं। अब राजस्थान के इसी गौरवशाली इतिहास को बड़े पर्दे पर जीवंत करने की तैयारी की जा रही है। निर्देशक नरेंद्र सिंह मीणा पहली बार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित फीचर फिल्म ‘शासक’ लेकर आ रहे हैं।



फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। इसमें अभिनेता मुकेश चावंडिया मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म को भव्य ऐतिहासिक ऐक्शन फिल्म के रूप में तैयार किया जा रहा है।

दीपावली पर आतिशबाजी के विरोधियों को सीएम योगी ने दिया जवाब

अरे प्रदूषण हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा, काहे चिंता कर रहे

लखनऊ (एजेंसी)। अगर पब्लिक एक दिन आतिशबाजी कर ले तो प्रदूषण हो गया, अरे हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा...। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें बुधवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं।

सीएम योगी ने इस दौरान राजस्व विभाग के लिए चुने गए 1146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 215 करोड़ रुपये



की सहायता राशि का भी वितरण किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने दीपावली पर पटाखे जलाने के मुद्दे पर भी अपने अंदाज में जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा, साल 2017 से पहले कोई भी त्योहार आता था, चाहे होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, क्रिसमस हो, ईद हो, गुरु पर्व हो या मकर संक्रांति, हर त्योहार से पहले दंगे शुरू हो जाते थे। पीएसी बल दंगाइयों का काल था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने यूपी पीएसी की 34 कंपनियां भी समाप्त कर दी। महीनों-महीनों तक कर्फ्यू लगे रहते थे, लेकिन अब आपने देखा होगा कि धनतेरस के दिन पूरी मार्केट में चहल-पहल थी। अयोध्या का दीपोतस्व बढ़िया रहा।

मैं भी अयोध्या में आतिशबाजी में था

अपने भाषण में सीएम योगी ने आगे कहा, आप सभी ने दीपावली मनाई और कुछ लोग कह रहे हैं कि पटाखे जलाने से प्रदूषण हो गया। अरे प्रदूषण हुआ है तो समाप्त भी हो जाएगा। काहे चिंता कर रहे हो, जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट कारनामों से पूरे सिस्टम को प्रदूषित किया, उन्हें कोई नहीं बोलता। अगर लोगों ने एक दिन पटाखे जला लिए तो प्रदूषण हो गया, अरे हुआ है तो खत्म भी हो जाएगा। अच्छा हुआ, लोगों ने खूब आतिशबाजी की और दीपावली धूमधाम से मनाई। हमने भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, खूब आतिशबाजी करो। मैं भी अयोध्या में आतिशबाजी में था। जब कुछ गलत होता है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई त्योहार मनाता है तो प्रदूषण याद आता है।

नो कर्फ्यू-नो दंगा यूपी में अब सब चंगा

सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा, पहले की सरकारों में कर्फ्यू की वजह से व्यापार प्रभावित होता था, त्योहार प्रभावित होते थे। लेकिन, पिछले साढ़े 9 साल में नो कर्फ्यू-नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा। चंगा है तो अब नौकरियां भी उसी रफ्तार से निकल रही हैं। अकेले राजस्व विभाग में अभी तक 10836 नियुक्तियां हुई हैं। 1146 नियुक्तियां आज हो रही हैं। आने वाली 26 जनवरी तक हर पांचवें दिन नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा।

फेस्टिव सीजन खत्म, अब यूपीआई पेमेंट पर जल्द लग सकता है चार्ज

2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4 फीसदी एमडीआर देना होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाईदूज के त्योहार के साथ ही फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है। अब सबकी नजरें यूपीआई के नए नियमों पर हैं। कल से दुकानदार को 2,000 से ज्यादा का यूपीआई के



जरिए लेने पर 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी चार्ज देना पड़ सकता है। पहले एनपीसीआई इन नए चार्जेस को 15 अक्टूबर से लागू करने वाला था, लेकिन त्योहारों के कारण इसे टाल दिया गया था। एनपीसीआई ने कहा था कि इसे दिवाली के तुरंत बाद लगाया जाएगा, हालांकि तारीख नहीं बताई गई है।

केंद्र सरकार के यूपीआई प्रपोजल की 3 बड़ी बातें

अगर ग्राहक दुकानदार को 2,000 से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करता है, तो दुकानदार को कुल रकम पर 0.4 फीसदी का एमडीआर चार्ज देना होगा। अगर ग्राहक 75,000 या उससे ज्यादा का बड़ा पेमेंट करता है, तो प्रतिशत के बजाय अधिकतम 300 का फ्लैट चार्ज लागू होगा। अगर ग्राहक रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस या फ्यूल पर 2,000 से ज्यादा का पेमेंट करता है, तो प्रति ट्रांजेक्शन 5 का फ्लैट चार्ज लगेगा। दिवाली के दौरान देश भर के बाजारों में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, गहने और सामानों की भारी बिक्री होती है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट बढ़ जाता है। कारोबारी संगठनों और पेमेंट कंपनियों का मानना था कि त्योहारों के बीच नया नियम लागू करने से दुकानों पर पेमेंट में रुकावट आ सकती है।

अब एनएसजी कमांडो की बदलेगी यूनिफॉर्म

44 डिग्री तापमान में जवान के बेहोश होने के बाद फैसला देश के 5 राज्यों में चुनाव से पहले मिल सकती है नई वर्दी

नई दिल्ली (एजेंसी)। ब्लैक कैट कमांडो की मशहूर काली वर्दी अब बदलने जा रही है। वजह है- भयंकर गर्मी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) ने अपने वीआईपी सुरक्षा में लगे कमांडो के लिए नई ब्रीदेबल यानी सांस लेने वाली यूनिफॉर्म बनाने की सिफारिश की है। ये यूनिफॉर्म नायको कपड़े से बनेगी, जिसमें नायलॉन और कॉटन होता है। यह कपड़ा हवा और नमी को आसानी से बाहर निकलने देता है। अप्रैल में विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा में तैनात कमांडो करीब 44 डिग्री तापमान में बेहोश हो गया था। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया। एनएसजी को उम्मीद है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा तक कमांडो नई यूनिफॉर्म पहनने लगेंगे।



काशी विश्वनाथ कॉरिडोर संजय गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था:सोनिया

कांग्रेस नेता ने अपनी किताब में किया जिक्र, तोड़फोड़ के विरोध पर इंदिरा ने रुकवाया

वाराणसी (एजेंसी)। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े पुराने प्रस्ताव का जिक्र किया है। उन्होंने इसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल से जोड़ते हुए आपातकाल के दौरान इसकी योजना बनाए जाने की बात लिखी है। किताब में लिखा- आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने काशी विश्वनाथ क्षेत्र के चौड़ीकरण और वहां सुधार का प्रस्ताव रखा था। विश्व के सबसे प्राचीन शहर में मकानों की भारी तोड़फोड़ और जनता के विरोध की आशंका को देखते हुए इंदिरा गांधी ने इसमें हस्तक्षेप किया था और उस काम को रुकवा दिया था।

बनारस रोड शो में बेहोश हुई थीं,कंधे में हुआ था फ्रैक्चर- सोनिया गांधी ने अपनी किताब में अगस्त 2016 के वाराणसी दौरे के दौरान हुई



घटना का भी जिक्र किया है। उस समय सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रोड शो से पहले सोनिया गांधी ने वाराणसी में चुनावी रैली की थी। किताब में लिखा है कि करीब पांच घंटे लंबे रोड शो के दौरान अत्यधिक थकान के कारण सोनिया गांधी बेहोश होकर गिर गई थीं। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया गया था। उनका कंधा बुरी तरह टूट गया था, जिसके चलते उन्हें गंभीर ऑपरेशन से गुजरना पड़ा था। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एक होटल में रखा गया।

असम में ट्रेन पटरी से उतरी, 50 पैसेंजर घायल

लोको पायलट बोले-सिग्नल रेड है, ब्रेक नहीं लग रहे

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम के कामरूप में बुधवार सुबह करीब 6.54 बजे कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे में 50 पैसेंजर घायल हुए हैं। हालांकि रेलवे का कहना है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुताबिक, डिगारू स्टेशन पर ट्रेन को दूसरी लाइन पर लेने के दौरान लोको पायलट स्पीड कम नहीं कर सका, इससे ट्रेन डेड एंड पर लगे बैरिकेड्स से टकरा गई। 45 सेकेंड के वीडियो में इंजन के लोको पायलट केबिन का अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसमें कंट्रोल पैनल, डिजिटल डिस्प्ले, स्विच और इंजन के उपकरण लगे हुए हैं।





छठ पूजा करने की सुविधा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : विजेंद्र गुप्ता

'पर्व शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जानी चाहिए'

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि छठ पूजा गहरी आस्था और श्रद्धा का पर्व है। प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। पर्व शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जानी चाहिए, ताकि सार्वजनिक सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। यह बात विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार को रोहिणी के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए कही। उल्लेखनीय है कि चार दिवसीय छठ पूजा का आयोजन 13 से 16 नवंबर तक किया जाएगा।



निरीक्षण के दौरान विजेंद्र गुप्ता ने सेक्टर-7 स्थित रामलीला मैदान, राजा विहार, सूरज पार्क, सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन के निकट तथा सेक्टर-15 के बी-ब्लॉक सहित पांच स्थानों का दौरा किया। उन्होंने छठ पूजा के मद्देनजर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, आवागमन की सुविधा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले सभी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह तैयार और क्रियाशील होनी चाहिए। विजेंद्र गुप्ता ने विभिन्न स्थानों पर तैयारियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित नागरिक एजेंसियों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी पांचों स्थानों पर निर्धारित समय से पहले आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जानी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

दिल्ली में हजारों परिवारों के लिए छठ पूजा के विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रशासन को श्रद्धालुओं की आवश्यकताओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहना चाहिए। उन्होंने महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से पूरी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया, ताकि 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ संपन्न होने वाला यह चार दिवसीय पर्व शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक ढंग से संपन्न हो सके।

महापौर ने मल्कागंज वार्ड का किया निरीक्षण

• अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के दिये आदेश

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने उत्तरी क्षेत्र में स्थित मल्कागंज वार्ड की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर प्रवेश वाही ने लगभग दो किलोमीटर चलकर मल्कागंज वार्ड की मुख्य सड़क पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया।

प्रवेश वाही ने मल्कागंज चौक पर स्थित पार्क से स्वयं मलबा हटाया एवं मुख्य मार्ग की जेटिंग मशीन से सफाई की। उन्होंने मल्कागंज मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण की स्थिति पर नाराजगी जताई और इसे तुरंत हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिक्रमण करने वालों के चालान करने के आदेश दिए। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महापौर ने एक स्वच्छता कर्मी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया एवं उसका नाम पुरस्कार के लिए भेजने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि बिना जनभागीदारी के यह कार्य संभव नहीं है। उन्होंने दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए जनता का सहयोग मांगा। साथ ही, महापौर ने तिमारपुर में स्थित बालकराम अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन एवं सीरम की प्रचुर उपलब्धता पर संतोष व्यक्त किया और लैब का भी निरीक्षण किया।



महापौर ने अस्पताल में आए रोगियों से बातचीत कर डाक्टरों एवं दवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। मुख्य सड़क से अस्पताल की अप्रोच रोड बनाने के कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निगम अपने अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के दौरान तिमारपुर के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री, स्थानीय पार्षद रेखा, अतिरिक्त आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल, उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त सचिन गुप्ता, अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ पूनम सरीन सहित दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अंतरराज्यीय अवैध दवा सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चार आरोपी दबोचे

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली के आर.के. पुरम स्थित क्राइम ब्रांच की एनडीआर (नारकोटिक्स ड्रग्स सेल) टीम ने एक अंतरराज्यीय अवैध दवा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 14.226 किलोग्राम अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल युक्त प्रतिबंधित दवाएं (कुल 21,180 गोलियां) बरामद की गईं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अपने एक आधिकारिक बयान में बताया कि यह ऑपरेशन एक एफआईआर के तहत चलाया गया, जो नई दिल्ली स्थित क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के विभिन्न इलाकों में संदिग्धों को पकड़ा गया और कई जगहों पर छापेमारी की गई। दर्ज एफआईआर और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की एनडीआर टीम को दिल्ली और आसपास के इलाकों में नशीली दवाओं (साइकोट्रोपिक पदार्थों) की अवैध खरीद, परिवहन, भंडारण और वितरण पर रोक लगाने का काम सौंपा गया था। इंस्पेक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम में सब इंस्पेक्टर अशोक, सौरभ, प्रमोद और यतेंद्र मलिक; असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विकास और कमल तथा हेड कांस्टेबल रविंदर, संजय, दिनेश, संदीप, राहुल, संजू, सुखबीर, नहानजी और भाग सिंह शामिल थे। यह पूरी कार्रवाई क्राइम ब्रांच के एसीपी/एनडीआर, उमेश बर्थवाल की सीधी देखरेख में संपन्न हुई। तकनीकी खुफिया जानकारी, निगरानी और गुप्त सूत्रों से मिले इनपुट के आधार पर टीम ने कई अभियान चलाए। इसके परिणामस्वरूप चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान मुनेश कुमार गुप्ता, अखिलेश मिश्रा, वीरेंद्र कुमार उर्फ 'हीरो' और राजेश्वर पांडे उर्फ 'गोपाल' के रूप में हुई है।

छठ पूजा की तैयारियों का मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने हाथी घाट पर लिया जायजा

घाट पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बुधवार को आईटीओ स्थित हाथी घाट का दौरा कर वहां छठ पूजा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने घाट पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली में लाखों श्रद्धालुओं के छठ पूजा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए सरकार द्वारा राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। छठ पूजा के लिए दिल्ली में कुल 996 स्थानों पर 1,482 घाटों की व्यवस्था की गई है। इनमें 53 स्थानों पर 81 स्थायी घाट, 914 स्थानों पर 1,372 अस्थायी घाट और यमुना नदी के किनारे 29 स्थानों पर 29 घाट शामिल हैं। तैयारियों को समय पर पूरा करने और व्यवस्थाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 74 एजेंसियों को लगाया गया है और 155 कार्य आवंटित किए गए हैं।



सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा घाटों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, साफ-सफाई और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। तैयारियों के तहत घाटों की साफ-सफाई, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, श्रद्धालुओं के आने-जाने की सुविधा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, वहां व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दोनों विभागों के बीच समन्वय के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूजा से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो जाएं और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि छठ पूजा दिल्ली में रहने वाले लाखों परिवारों, विशेषकर हमारे पूर्वांचली भाई-बहनों के लिए बहुत भावनात्मक और आस्था से जुड़ा पर्व है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का यह अवसर हर परिवार के लिए बहुत खास होता है। इसी उद्देश्य से दिल्लीभर में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने और हर घाट पर श्रद्धालुओं की जरूरतों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सभी निर्धारित घाटों पर तैयारियों को पूरा करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, ताकि राजधानी के श्रद्धालु स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण में छठ महापर्व मना सकें।

एमसीडी की आय बढ़ाने के लिए एआई का सहारा

180 दिन के पायलट प्रोजेक्ट से होगी विज्ञापन स्थलों की डिजिटल मैपिंग

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और राजस्व के नए स्रोत विकसित करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और आधुनिक तकनीक का सहारा लेगा। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने जानकारी दी कि आउटडोर विज्ञापन व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए 180 दिन का पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके तहत दिल्ली में होर्डिंग, यूनिपोल, कियोस्क और स्ट्रीट फर्नीचर सहित सभी आउटडोर विज्ञापन स्थलों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। सत्या शर्मा ने कहा कि एमसीडी के पास राजस्व अर्जित करने के कई संसाधन हैं, लेकिन उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। विज्ञापन क्षेत्र में एआई, जीआईएस मैपिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग के इस्तेमाल से न केवल आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि राजस्व के नुकसान को रोकने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए आर3 इंटरएक्टिव मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 180 दिन के पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत निजी एजेंसी अपने खर्च पर विज्ञापन परिसंपत्तियों का सर्वे, जियो-टैगिंग और जीआईएस आधारित मैपिंग करेगी। खास बात यह है कि इस परियोजना पर एमसीडी को कोई वित्तीय खर्च नहीं करना होगा। प्रस्ताव को स्थायी समिति के माध्यम से निगम की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है। एमओयू के मसौदे में निगम के विधि एवं वित्त विभाग के सुझाव भी शामिल किए गए हैं। इस परियोजना में एजेंसी के एआई आधारित विजुअल लोड इंडेक्स (वीएलआई) टूल की अहम भूमिका होगी। यह टूल सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे विज्ञापनों की संख्या, दृश्यता और उनसे पैदा होने वाली दृश्य अव्यवस्था का विश्लेषण करेगा। इसके आधार पर ऐसे स्थानों और विज्ञापन कॉरिडोर की पहचान की जाएगी, जहां विज्ञापन लगाने की अधिक व्यावसायिक संभावनाएं मौजूद हैं।



वहीं, जिन इलाकों में विज्ञापनों की अधिकता है, वहां उनकी संख्या और स्थान को व्यवस्थित करने के सुझाव भी मिलेंगे। इससे निगम को विज्ञापन स्थलों की नीलामी, मूल्यांकन और टेंडर प्रक्रिया की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। परियोजना के तहत 360 डिगी वर्चुअल सर्वे के जरिए प्रत्येक विज्ञापन स्थल की तस्वीरें, लोकेशन, आकार, रोशनी और नियमों के अनुपालन से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। जीआईएस मैपिंग और जियो-टैगिंग के माध्यम से सभी विज्ञापन परिसंपत्तियों का केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा। इसके अलावा डैशबोर्ड, हीट मैप और एनालिटिक्स रिपोर्ट के जरिए विज्ञापन स्थलों की निगरानी और प्रबंधन किया जा सकेगा।

डिजिटल डेटाबेस का पंजीकृत विज्ञापन स्थलों के रिकॉर्ड से मिलान कर अनधिकृत विज्ञापन संरचनाओं की पहचान की जाएगी। इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान होगा और निगम को होने वाले राजस्व नुकसान पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

दिल्ली में प्रदूषण पर आआपा का सरकार पर निशाना, कहा-

जनता को स्वच्छ हवा देना सरकार की जिम्मेदारी

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी (आआपा) ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में नेता प्रतिपक्ष और आआपा नेता अंकुश नारंग ने सिविक सेंटर में आयोजित पत्रकार को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है। दिवाली की रात पटेल नगर में एक्यूआई 1870 तक पहुंचने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 500 के पार दर्ज किया जा रहा है। इससे लोगों को सांस



लेने में परेशानी हो रही है और अस्थमा व अन्य सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।

नारंग ने कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी को प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि सड़कों पर पानी का छिड़काव, धूल नियंत्रण और प्रदूषण कम करने के लिए प्रभावी इंतजाम पर्याप्त रूप से क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। नारंग ने वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जहांगीरपुरी के एक मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी का छिड़काव किए जाने से आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने दिवाली के दिन कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों के बंद रहने का मुद्दा उठाते हुए इसकी जांच कराने और प्रदूषण के वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की।

आआपा नेता ने कहा कि प्रदूषण का सीधा असर दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एमसीडी को मिलकर तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई करने की भी मांग की। अंकुश नारंग ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव, धूल प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। साफ हवा दिल्लीवासियों का अधिकार है और सरकार को इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए।

छठ पूजा पर 16 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय में छुट्टी

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने छठ पूजा के मौके पर सोमवार (16 नवंबर) को छुट्टी घोषित कर दी है। यह छुट्टी उच्च न्यायालय के साथ-साथ इसके अधीन आने वाली सभी अधीनस्थ अदालतों में भी लागू रहेगी। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल रीतेश सिंह की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, 16 नवंबर की छुट्टी के बदले इस छुट्टी के बदले शनिवार (21 नवंबर) को उच्च न्यायालय खुला रहेगा और सामान्य रूप से कामकाज होगा। 16 नवंबर को जिन मामलों की सुनवाई तय थी, वो अब मंगलवार 17 नवंबर को सुने जाएंगे।

दीपावली के मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के 141.88 करोड़ रुपये 15 लाख लाभार्थियों के खातों में भेजे गए

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 15 लाख से अधिक पात्र राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि भेजी। लाभार्थियों को सांकेतिक चेक भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर दिल्ली के खाद्य-आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, कुलदीप सोलंकी, चंदन चौधरी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने घोषित संकल्पों को पूरा करने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राशन कार्डधारक परिवारों को होली और दीपावली पर आर्थिक सहायता देने की योजना इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। सहायता राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित करने से लाभार्थियों तक आर्थिक सहयोग पहुंचाने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनती है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने राशन कार्डधारक परिवारों को होली और दीपावली पर एलपीजी सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई थी। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष दीपावली के अवसर पर दिल्ली के 15,45,994 परिवारों के बैंक खातों में कुल 141.88 करोड़ रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1,24,964 परिवार और नॉन पीएमयूवाई श्रेणी के 14,21,030 परिवार शामिल हैं। इनमें पीएमयूवाई श्रेणी के प्रत्येक परिवार को 642 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं नॉन पीएमयूवाई श्रेणी के प्रत्येक परिवार को 942 रुपये की सहायता राशि दी गई। इसका उद्देश्य वर्ष में दो प्रमुख त्योहारों पर परिवारों को आर्थिक सहयोग देना और घरेलू खर्च का बोझ कम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने योजना के अंतर्गत सहायता राशि हस्तांतरित करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था अपनाई है। इसके माध्यम से राशि परिवार के मुखिया के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे पहुंचाई जाती है। उन्होंने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन में लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड संबंधी विवरणों का सत्यापन और आवश्यक डेटा का मिलान किया जाता है, ताकि निर्धारित पात्र परिवारों तक सहायता पहुंच सके। साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने और किसी प्रकार की दोहरी सहायता, राशि के दुरुपयोग या अनियमितता को रोकने के लिए निगरानी एवं ऑडिट की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है।

उपराज्यपाल ने लोधी गार्डन में बागवानी से जुड़ी विभिन्न पहलों का लिया जायजा

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने लोधी गार्डन में दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की नर्सरी का दौरा किया। उन्होंने वहां बागवानी से जुड़ी विभिन्न पहलों का जायजा लिया। इसमें हाई-टेक नर्सरी, ट्यूलिप ग्रोथ-कम-स्टोरेज चैंबर, कम्पोस्टिंग सुविधाएं, कैक्टस हाउस और 'ट्री एम्बुलेंस' शामिल हैं।

उपराज्यपाल ने एनडीएमसी को ट्यूलिप उगाने की एक स्वदेशी प्रक्रिया विकसित करने, मौसमी फूलों का दायरा बढ़ाने और स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने स्थानीय ट्यूलिप की खेती को बढ़ावा देने, बागवानी क्षमताओं को मजबूत करने और शहर के हरित क्षेत्रों को संरक्षित करने



की दिशा में एनडीएमसी के प्रयासों की भी सराहना की। इस दौरे के दौरान एनडीएमसी अध्यक्ष एम के द्विवेदी, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल और परिषद के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर ने बागवानी में नवाचार, टिकाऊ हरित प्रथाओं और नई दिल्ली को अधिक स्वच्छ, हरित और सुंदर बनाने के प्रति एनडीएमसी की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। इससे पहले उपराज्यपाल ने आज कड़कड़डूमा में 'ईस्ट दिल्ली हब' के एकीकृत विकास की समीक्षा की। इस दौरान विधायक ओपी शर्मा, वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर भी मौजूद रहे। उन्होंने यहां सार्वजनिक परिवहन संपर्क को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत आवासीय टावरों, नागरिक सुविधाओं और हरित क्षेत्रों के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया।

'स्थानीय ट्यूलिप की खेती को बढ़ावा देने, बागवानी क्षमताओं को मजबूत करने और शहर के हरित क्षेत्रों को संरक्षित करने की दिशा में एनडीएमसी के प्रयासों की भी सराहना की।'

उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी एबीसीसी को निर्देश दिए कि वे आपसी तालमेल बेहतर रखें, लंबित कानूनी मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाएं और समय पर प्रोजेक्ट पूरा करके इसे सौंपें।

उन्होंने पूर्वी दिल्ली, टिकाऊ और सुव्यवस्थित शहरी जीवन का एक बेहतरीन उदाहरण बनेगी। प्रोजेक्ट का परिणाम, तय किए गए विजन के अनुरूप ही होना चाहिए। यह विकसित दिल्ली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संक्षिप्त डायरी

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर न्याय को सभी के लिए सुलभ बनाने का संकल्प

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरुक करने और समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष विधिक जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं डीएलएसए के अध्यक्ष नरेंद्र सुरा ने कहा कि न्याय तक समान पहुंच लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण आधारशिला है। विधिक सेवा संस्थाओं का दायित्व है कि वे आम नागरिक और न्याय व्यवस्था के बीच की दूरी को कम करते हुए प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक न्याय एवं कानूनी सहायता पहुंचाएं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने जमीनी स्तर पर विधिक जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कानूनी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सशक्त बनाती है। इससे नागरिक समय पर उचित कानूनी सहायता एवं उपचार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह दिवस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक अथवा अन्य असमर्थता के कारण न्याय से वंचित न रहे।\

सात माह बाद भी ड्राइवर कल्याण बोर्ड नहीं हुआ लागू: योगेश शर्मा

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक एवं महान राष्ट्रवादी श्रमिक चिंतक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जयंती पर बुधवार को हरियाणा ऑटो चालक संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के कार्यकताओं की बैठक हुई। यहां देवीलाल कॉलोनी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कुलदीप यादव ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। बैठक में बतौर मुख्य वक्ता भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष योगेश शर्मा उपस्थित रहे। बैठक का संचालन अनिल कुमार ने किया। अपने संबोधन में योगेश शर्मा ने कहा कि परम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कर देश के श्रमिक आंदोलन को एक नई वैचारिक दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि सात माह बीतने के बाद भी हरियाणा सरकार ने ड्राइवरों के लिए कल्याण बोर्ड को लागू नहीं किया। ऑटो चालकों के लिए स्थाई स्टैंड पिछले सात साल से नहीं बने। उन्होंने कहा कि सरकार घोषणाएं तो करती है, लेकिन जमीन पर उन्हें लागू नहीं करती। इससे ड्राइवरों में भारी रोष है। योगेश शर्मा ने आगामी 19 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले एक दिवसीय राष्ट्रीय महाधरने में हरियाणा से अधिक से अधिक संख्या में ड्राइवरों एवं कार्यकताओं को भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय महाधरने में देश के लगभग 22 प्रदेशों से भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि भाग लेंगे तथा केंद्र सरकार को ड्राइवरों की समस्याओं और अधिकारों से संबंधित 11 सूत्रीय मांगपत्र सौंपेंगे।

गुरुग्राम के शीतला माता अस्पताल में आयुष्मान लाभार्थियों को इलाज में मिलेगी सब्सिडी

एजेंसी

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि गुरुग्राम के सेक्टर-102 स्थित श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं 883 बेड के टीचिंग अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों तथा पांच लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के पात्र मरीजों के लिए उपचार संबंधी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनके माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को उपचार में सब्सिडी का लाभ मिलेगा और वे किफायती दरों पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में मेडिकल कॉलेज एवं टीचिंग अस्पताल के संचालन और रखरखाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों तथा पांच लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के पात्र मरीजों के लिए उपचार में सब्सिडी और अस्पताल में विशेष सुविधाओं से संबंधित प्रावधानों पर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल परिसर में अमृत फार्मेसी खोलने के निर्देश भी दिए, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपचार के साथ-साथ मरीजों को दवाइयों की उपलब्धता भी सहज और किफायती होनी चाहिए। बैठक में मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों के दाखिले के लिए सीटों और फीस से संबंधित प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सीटों तथा फीस संरचना को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए ।

पटौदी जटौली अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद अस्थायी बंद

एजेंसी

गुरुग्राम। राज्य सरकार के निदेर्शानुसार बाजरे की सरकारी खरीद फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। बाजरे की खरीद के लिए संचालित ई-खरीद पोर्टल को भी आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसके चलते फिलहाल बाजरे के गेटपास जारी नहीं हो सकेंगे। मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएम) पंचकूला द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी पत्र के माध्यम से राज्य की मंडियों में बाजरे की खरीद बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पटौदी जटौली अनाज मंडी में भी बाजरे की खरीद प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी। मार्केट कमेटी पटौदी के चेयरमैन मनोज मोकलवास ने बताया कि यदि कोई वास्तविक किसान किसी कारणवश अपनी बाजरा फसल बेचने से वंचित रह गया है, तो ऐसे मामलों का सत्यापन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के उपरांत अनुमोदित किसानों की सूची हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भेजी जाएगी, ताकि पात्र किसानों को ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से बाजरा बेचने की अनुमति मिल सके।मार्केट कमेटी सचिव विपिन यादव ने बताया कि किसानों को खरीद प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए मार्केट कमेटी कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल दोबारा शुरू होने और खरीद संबंधी आगामी दिशा-निर्देश जारी होने पर किसानों को इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि बिना पुष्टि किए बाजरा मंडी में न लाएं, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

धूल नियंत्रण नियमों की अनदेखी पर पांच निर्माण स्थल सील

एजेंसी

गुरुग्राम। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुरुग्राम (उत्तर) की टीम ने धूल नियंत्रण से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने वाले पांच प्रमुख निर्माण स्थलों को सील कर दिया। बोर्ड की कार्रवाई से शहर के बिल्डर्स और निर्माणकताओं में हड़कंप मच गया है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, औचक निरीक्षण के दौरान इन निर्माण स्थलों पर प्रदूषण रोकने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं पाए गए। इसके अलावा, ये सभी साइटें प्रदूषण बोर्ड के आधिकारिक डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण और उससे जुड़े मानकों के अनुपालन की अनिवार्य शर्तों को पूरा करने में भी पूरी तरह विफल रहीं। कार्रवाई के तहत सील किए गए पांच निर्माण स्थलों में से तीन अकेले उद्योग विहार क्षेत्र में स्थित हैं, जहां व्यावसायिक निर्माण कार्यों के दौरान खुले में धूल उड़ाई जा रही थी और पर्यावरण नियमों की खुली अनदेखी हो रही थी। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण सुरक्षा और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान या बिल्डर को बख्शा नहीं जाएगा। महज एक सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह ताबड़तोड़ कार्रवाई दिखाती है

ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो को कैबिनेट की मंजूरी, 8.5 किमी रूट पर बनेंगे 5 स्टेशन, दो लाख से अधिक लोगों को मिलेगा फायदा

अनप्लग इंडिया।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 (किसान चौक) तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। करीब 8.5 किलोमीटर लंबे इस रूट पर पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। लगभग 2,390 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से दो लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण से नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस परियोजना को लेकर लंबे समय से स्थानीय निवासी और सामाजिक संगठन मांग उठा रहे थे।

इन पांच स्थानों पर बनेंगे मेट्रो स्टेशन

प्रस्तावित कॉरिडोर पर कुल पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें शामिल हैं:

सेक्टर-61
सेक्टर-70
सेक्टर-122
सेक्टर-123
ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 (किसान चौक के पास)



परियोजना पूरी होने के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट के तेजी से विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्रों को नोएडा से बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

गौड़ चौक के जाम से राहत मिलने की उम्मीद

ग्रेटर नोएडा वेस्ट से नोएडा आने-जाने वाले लोगों को रोजाना ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। खासकर गौड़ चौक और आसपास की सड़कों पर वाहनों का दबाव अधिक रहता है। फिलहाल बड़ी संख्या में लोग निजी वाहनों से सफर करते हैं।

मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद लोगों को सार्वजनिक परिवहन का बेहतर विकल्प मिलेगा। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है।

केंद्र और राज्य सरकार सहित चारों की रहेगी हिस्सेदारी

इस मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की हिस्सेदारी रहेगी। इक्विटी के आधार पर चारों मिलकर परियोजना के लिए बजट उपलब्ध कराएंगे।

नेफोमा ने जताया आभार, अन्नू खान बोले- दिवाली का यादगार उपहार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो की मांग को मंजूरी मिलने पर नेफोमा (नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स मेन एसोसिएशन) ने खुशी जताई है। संगठन के अध्यक्ष अन्नू खान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्थानीय सांसद डॉ. महेश शर्मा का आभार व्यक्त किया।

अन्नू खान ने कहा, 'कई वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद आज मोदी मंत्रिमंडल ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो की मांग को मंजूरी दे दी है। सेक्टर-51 से सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो कॉरिडोर पास होना क्षेत्र के निवासियों के लिए बड़ी राहत है। इसके लिए हम मोदी मंत्रिमंडल और स्थानीय सांसद डॉ. महेश शर्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। '

उन्होंने कहा कि मेट्रो आने से लाखों निवासियों को फायदा मिलेगा और ट्रैफिक जाम से निजात मिलने की उम्मीद है। दिवाली के मौके पर मिला यह उपहार ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जनता हमेशा याद रखेगी।

अन्नू खान ने कहा कि यह फैसला क्षेत्र के विकास और बेहतर सार्वजनिक परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल



अनप्लग इंडिया

नोएडा। सेक्टर-24 थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन के चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घायल की पत्नी ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सेक्टर-34 स्थित उदयगिरी अपार्टमेंट में रहने वाली शानू पटनी ने पुलिस को बताया कि उनके पति नौ नवंबर को अपनी बाइक से नोएडा सिटी सेंटर से अपने घर आ रहे थे। जब वह सुरभि अस्पताल के सामने नाले के पुल के पास पहुंचे तो पीछे से एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इसके चलते उन्हें गंभीर चोट आई। बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें फौरन ही सुरभि अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार दिलाया। इसके बाद उन्हें सेक्टर-71 स्थित कैलाश अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उनके पति की हालत गंभीर है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से वाहन चालक की पहचान की जा रही है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रदूषण फैलाने वालों पर 17 दिन में लगाया 45.82 लाख रुपये जुमार्ना

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की प्रवर्तन टीमें प्रदूषण और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी कड़ी में 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 2026 तक 17 दिन में विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों पर कुल 634 चालान जारी किए गए। चालान काटकर 45,82,300 रुपये का जुमार्ना लगाया गया। यह कार्रवाई शहर में स्वच्छता नियमों का पालन सुनिश्चित कराने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई। नगर निगम की प्रवर्तन टीमों ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग के मामलों में 177 चालान जारी किए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के 88 और डस्ट मिटिगेशन नियमों की अवहेलना के 85 मामलों में कार्रवाई की गई। इसके अलावा कूड़ेदान उपलब्ध नहीं होने पर 80 चालान किए गए।



खुले में कचरा जलाने के 54 मामलों में कार्रवाई की गई, जबकि पानी की बबार्दी करने वालों के खिलाफ भी 54 चालान जारी किए गए। निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) वेस्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर 22 तथा निर्माण कार्य बंद करने के आदेशों की अवहेलना करने पर 11 चालान किए गए। निगम की कार्रवाई में बिना ढके निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहन, अवैध रूप से कचरा डालने, स्टॉर्म वाटर ड्रेन में अवैध कनेक्शन, खुले में शौच, सेप्टेज संबंधी उल्लंघन और अन्य स्वच्छता नियमों के मामले भी शामिल रहे। एमसीजी की ओर से दावा किया गया है कि सडकों को धूल मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नियमित रोड स्वीपिंग, प्रमुख सडकों पर पानी का छिडकाव, सडक किनारों पर जमा मिट्टी को हटाने और धूल नियंत्रण के अन्य उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एंटी-स्मॉग गन भी तैनात की गई हैं। इनके माध्यम से धूल कणों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निगम की टीमें सडकों और आसपास के क्षेत्रों की नियमित सफाई कर रही हैं, ताकि धूल के स्रोतों को कम किया जा सके और नागरिकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। धूल नियंत्रण अभियान की जमीनी स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त अंकिता चौधरी ने जोन-3 में डस्ट एक्शन प्लान के तहत चिन्हित सडकों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर धूल नियंत्रण के उपायों की स्थिति का जायजा लिया और अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की।

गुरुग्राम में अब हर 60 दिन में होगा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का तबादला

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। भ्रष्टाचार के विरुद्ध गुरुग्राम पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए बड़े और सख्त कदम उठाए हैं। ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान किसी भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी, होमगार्ड या एसपीओ की संलिप्तता पाए जाने पर अब जोनल ऑफिसर (जेडओ) और ट्रैफिक इंस्पेक्टर (टीआई) की भी जिम्मेदारी तय होगी। साथ ही बॉडी वार्न कैमरा के बिना वाहन रुकवाने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इस तरह के आदेश पुलिस आयुक्त शिवास कविराज की ओर से दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त शिबास कबिराज ने भ्रष्टाचार, लापरवाही, अवैध वसूली, अनुचित व्यवहार सहित किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अधिकारियों को आदेश देते हुए पुलिस आयुक्त शिवास कविराज ने कहा कि एसीपी स्तर के अधिकारी सीसीटीवी कंट्रोल रूम के माध्यम से भ्रष्टाचार निरोधी निगरानी करेंगे। साथ ही प्रत्येक 60 दिन के बाद स्वचालित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का तबादला होगा। सोशल मीडिया पर होमगार्ड द्वारा उपहार के नाम पर अवैध वसूली करने के संबंध में वायरल हुई वीडियो के आधार पर त्वरित कार्यवाही



करते हुए आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार करने के साथ ही गुरुग्राम पुलिस के सभी डीसीपी, एसीपी के माध्यम से ग्राउंड लेवल के पुलिसकर्मियों को सख्त आदेश दिए हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित क्षेत्र के जेडओ एवं टीआई की जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम में एसीपी रैंक के अधिकारी सभी सीसीटीवी कैमरों की नियमित रूप से जांच एवं निगरानी सुनिश्चित करेंगे, ताकि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नजर रखी जा सके। यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्यवाही बॉडी वार्न कैमरे की निगरानी में करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे तथा वाहनं चालकों एवं पुलिसकर्मियों दोनों के हित सुरक्षित रहें। सीपी शिवास कविराज ने ड्यूटी में पारदर्शिता बनाए रखने, किसी एक स्थान पर लंबे समय तक तैनाती से उत्पन्न होने वाली अनियमितताओं की संभावनाओं को कम करने तथा निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 60 दिन में रैंडम कंप्यूटरीकृत ट्रांसफर की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज का नियमित विश्लेषण करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा अनियमितता के सामने आने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए

छठ घाटों पर साफ-सफाई शुरू, तीन दिन बाद भरे जाएंगे पानी

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी में लोक आस्था का पर्व छठ शुक्रवार को संकल्प व्रत से आरंभ होगा। इसको लेकर छठ घाटों पर साफ सफाई शुरू हो गई। तीन दिन बाद इनमें पानी भरा जाएगा। वहीं छठ पर्व को लेकर सजे बाजार में बांस निर्मित सूप-दउरा की खरीदारी शुरू हो गई है। छठ पूजा की तैयारियां और बाजार सदर बाजार के सब्जी मंडी में सूप, छांटी टोकरी, डगरा और दउरा की दुकानें सजने लगी है। बाजार में बांस से बने सूप, दउरी, नारियल, गन्ना, फलों की दुकानें सजने लगीं है। दुकानदार राम कुमार ने कहा कि गुरुग्राम में छठ के मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग नहीं होते है। सिर्फ मिट्टी के दीये, सूप, दउरा, टोकरी ज्यादा बिकते है। उन्होंने छठ के बाजार में दूसरे राज्यों से आने वाले उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ, अलीगढ़, आगरा समेत अन्य जिलों से बास के बने सामान आते है। लोग खरीदारी करने के लिए आने शुरू हो गए हैं। घाट पर अलग-अलग शौचालय शहर में छठ पूजा के आयोजन को लेकर समितियां सक्रिय हो गई हैं। चार दिवसीय अनुष्ठान शुक्रवार 13 नवंबर को नहाय-खाय से शुरू होगा। यह 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ पूरा होगा। गुरुग्राम में कुल 31 पक्के और 60 से अधिक कच्चे स्थानों पर छठ पूजा के सामूहिक और बड़े आयोजन होंगे। सोमवार को बसई तालाब छठ पूजा समिति की बैठक हुई। समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने कहा कि बैठक में महापर्व को भव्य और व्यवस्थित बनाने पर चर्चा हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना था। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय होते है, पेयजल और रोशनी के इंतजाम किए जाएंगे। घाट पर सुरक्षा, बैरिकेडिंग, गोताखोर, नाव और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होगी। इन स्थानों पर बनाए जा रहे छठ घाट शीतला माता मंदिर पार्किंग एरिया, सेक्टर पांच लेबर चौक, न्यू पालम विहार, शक्ति पार्क, सूरत नगर फेज-2, कादीपुर सामुदायिक भवन सेक्टर-10, सरस्वती एन्क्लेव, चकरपुर गांव, कन्हई गांव, ओम विहार, राजेंद्रा पार्क, देवीलाल कॉलोनी और सेक्टर-15 पार्ट-2 में प्रमुख रूप से छठ घाट बनाए जाते हैं। इन स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटकर विधि-विधान से पूजा करते हैं। इसके अलावा शहर के अन्य आवासीय क्षेत्रों में भी अस्थायी घाट तैयार किए जा रहे हैं। निजी कोष से तालाब की खुदाई कराई राजेन्द्रा पार्क स्थित धर्म कांटे वाली गली मे छठ पूजा कमेटी ने अपने निजी कोष से तालाब की खुदाई व इस जगह-जगह की साफ-सफाई कराया है। अभी केवल तालाब की खुदाई हो चुकी है। 14 नवंबर से तालाब में टैंकर से पानी भरा जाएगा। पूजा कमेटी अध्यक्ष राजेश पटेल ने बताया कि गत 2011 से राजेन्द्रा पार्क में छठ पूजा होता आ रहा है। यहां पर लगभग एक हजार श्रद्धालुओं की संख्या होती है। जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी होंगे अध्यक्ष ने कहा कि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, पूरा ध्यान रखा जाता है। जो व्रती पूजा के लिए सहयोग चाहिए तो कमेटी से संपर्क सकती है। जरूरमंद को सहयोग राशि 1100 रुपये दिया जाता है। इसके लिए कुछ छठ हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते है, जो किसी आपात स्थिति में छठ पूजा के दौरान एम्बुलेंस निःशुल्क होते है।

नोएडा में धूमधाम से मनाया गया गोवर्धन पर्व: इस्कॉन मंदिर में खाद्य सामग्रियों से सजा 20 फीट लंबा गोवर्धन पर्वत, उमड़े श्रद्धालु

अनप्लग इंडिया

नोएडा। नोएडा दीपावली के ठीक अगले दिन नोएडा शहर में गोवर्धन पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न सेक्टरों के मंदिरों और ग्रामीण अंचलों में श्रद्धालुओं ने भगवान गोवर्धन की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिरों और घरों में अनूठे आयोजन देखने को मिले, जहां कहीं गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की गई, तो कहीं अनगिनत खाद्य सामग्रियों से भव्य झांकियां सजाई गईं। दिनभर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा और पूरा शहर भक्तिमय नजर



आया। इस्कॉन मंदिर में सजा 20 फीट लंबा गोवर्धन पर्वत सेक्टर-33 स्थित प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन पूजा का एक विशेष और भव्य आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में करीब 20 फीट लंबा, सात फीट चौड़ा और तीन फीट ऊंचा विशाल गोवर्धन पर्वत तैयार किया गया था। इस पर्वत को बनाने के लिए चीनी, मिश्री, सूजी का हलवा, चावल और अन्य लजीज खाद्य सामग्रियों का उपयोग किया गया, जिससे इसकी छटा देखते ही बन रही थी। इस्कॉन मंदिर में इस दौरान विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए: भव्य झांकी और दर्शन: श्रद्धालुओं ने गिरिराज के अलौकिक दर्शन किए और मंदिर परिसर में ही परिक्रमा लगाई। कीर्तन और कथा: भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए मंत्रमुग्ध कर देने वाले संकीर्तन और गोवर्धन कथा का आयोजन हुआ। 56 भोग और महाआरती: भगवान को छप्पन भोग अर्पित किए गए, जिसके बाद भव्य महाआरती संपन्न हुई। प्रसाद वितरण: पूजा के उपरांत गोवर्धन पर्वत के निर्माण में प्रयुक्त की गई पवित्र खाद्य सामग्रियों का महाप्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। विभिन्न सेक्टरों के मंदिरों में रही धूम इस्कॉन मंदिर के अलावा नोएडा के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी गोवर्धन पूजा का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। श्रीसिद्ध शनि मंदिर: इन मंदिरों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा-अर्चना कर परिक्रमा की और सुख-शांति का आशीर्वाद मांगा। ग्रामीण इलाकों और घरों में भी गूंजे जयकारे केवल मंदिरों तक ही यह उत्सव सीमित नहीं रहा, बल्कि नोएडा के विभिन्न गांवों और सोसाइटियों में भी लोगों ने पारंपरिक उल्लास के साथ गोवर्धन पूजा की। घरों में महिलाओं ने आंगन या छत पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उनका श्रृंगार किया और दीप प्रज्वलित किए। भगवान गोवर्धन को अन्नकूट और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। दीपावली के बाद आए इस पर्व पर दिनभर मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। चारों तरफ 'गोवर्धन महाराज की जय' के जयकारों से वातावरण गूंज उठा, जिससे पूरे शहर में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उल्लास का माहौल देखने को मिला।

संपादकीय

राम मंदिर की दहलीज पर अखिलेश की दस्तक, 2027 के चुनाव से पहले अयोध्या की ओर बढ़े कदमों ने छेड़ी नई राजनीतिक बहस

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या और श्रीराम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी एवं सांसद डिंपल यादव के साथ 12 दिसंबर को अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन करने की घोषणा की है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह उनका पहला दर्शन होगा। इस घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है कि आखिर अखिलेश यादव को अब अयोध्या की याद क्यों आई?



अयोध्या केवल एक धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। वर्षों के संघर्ष और लंबे न्यायिक विवाद के बाद यहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की पहचान विश्व स्तर पर स्थापित हुई। देश-विदेश से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर निर्माण ने भारतीय संस्कृति, आस्था और धार्मिक पर्यटन को नई पहचान दी है।

लेकिन इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के बीच समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंदिर से दूरी लगातार राजनीतिक चर्चा का विषय बनी रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को घेरते रहे हैं। भाजपा का आरोप रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने राजनीतिक समीकरणों के कारण राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व के मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने से परहेज किया। दूसरी ओर अखिलेश यादव भाजपा पर धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना रहा है कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और राजनीति में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस पूरे विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वर्ष 1990 की अयोध्या की घटना से जुड़ी है। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या पहुंचे कारसेवकों पर पुलिस ने गोली चलाई थी। इस घटना ने देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। भाजपा और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संगठन आज भी इस घटना को समाजवादी पार्टी के राजनीतिक इतिहास से जोड़कर उठाते हैं। मुलायम सिंह यादव के उस समय के फैसले को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद और आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के अवसर पर अखिलेश यादव की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि रामभक्तों और संतों पर लाठीचार्ज तथा कारसेवकों पर गोली चलाने वालों को अयोध्या आने से पहले रामभक्तों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम दयालु हैं और सभी को क्षमा कर देते हैं, लेकिन सत्ता का अहंकार समाप्त करने में भी देर नहीं लगाते। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव का नाम सीधे नहीं लिया,

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती ताकत और सुरक्षा का सवाल



महेन्द्र तिवारी
साहित्यकार एवं लेखक
पूर्व वायुसैनिक, नई दिल्ली

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विस्तार आज मानव सभ्यता के इतिहास में एक बड़े परिवर्तन का संकेत बन चुका है। विज्ञान और तकनीक की इस नई उपलब्धि ने मनुष्य के जीवन को जितना सरल, सुविधाजनक और गतिशील बनाया है, उतनी ही नई चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं। चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा और संचार जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अब मशीनें केवल मनुष्य के निर्देशों पर काम करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं निर्णय लेने, सूचनाएँ जुटाने, विश्लेषण करने और कई कार्यों को स्वतंत्र रूप से पूरा करने में सक्षम होती जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि यही तकनीक किसी दिन मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी गंभीर चिंता को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए कठोर सुरक्षा नियम बनाने और एक विशेष नियामक संस्था स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 10 नवंबर 2026 को घोषणा की कि उनकी सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग से जुड़े सुरक्षा मानकों को कानूनी रूप देने की तैयारी कर रही है। इसके अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने वाली कंपनियों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य बनाया जाएगा। साथ ही एक ऐसी नियामक संस्था स्थापित करने की योजना है, जो इन कंपनियों की गतिविधियों पर निगरानी रखेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर आर्थिक दंड लगाने में सक्षम होगी। सरकार गंभीर लापरवाही के मामलों में आपराधिक कानून में संशोधन की संभावना पर भी विचार कर रही है। यह पहल केवल किसी एक तकनीकी कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने की कोशिश है। इस निर्णय के पीछे एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने दुनिया का ध्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े संभावित खतरों की ओर आकर्षित किया। इस वर्ष जून में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वचालित प्रणाली ने ऑस्ट्रेलिया की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े मेडिकेयर सांख्यिकी पोर्टल तक अनधिकृत पहुँच बना ली थी। यह प्रणाली सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय से संबंधित जानकारी जुटाने के कार्य में लगी थी। जाँच में पता चला कि उसने कुछ ऐसी सरकारी सामग्री तक भी पहुँच बनाई, जिसकी अनुमति उसे नहीं थी। संबंधित कंपनी को इस घटना की जानकारी अगस्त में हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार को इसकी सूचना सितंबर में दी गई। कंपनी की जाँच में मरीजों के व्यक्तिगत अभिलेखों तक पहुँच के प्रमाण नहीं मिले। फिर भी सरकारी व्यवस्था में इस प्रकार की अनधिकृत पहुँच को गंभीर सुरक्षा चूक माना गया। सूचना देने में हुई देरी ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी। इस घटना ने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया कि जब कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली स्वयं निर्णय लेकर कार्य करने लगे और उसके निर्णय से किसी सरकारी व्यवस्था, संस्था अथवा नागरिक की निजता प्रभावित हो, तब उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या केवल उस तकनीक को विकसित करने वाली कंपनी को उत्तरदायी माना जाएगा या उस कंपनी के संचालकों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? अब तक तकनीकी कंपनियाँ अपनी प्रणालियों की सुरक्षा और उनसे जुड़ी घटनाओं की जानकारी देने के मामले में काफी हद तक स्वयं निर्णय लेती रही हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार का मानना है कि जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। किसी भी कंपनी को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह अपनी सुविधा के अनुसार सुरक्षा संबंधी घटना की जानकारी दे या उसे छिपाए रखे। सरकार द्वारा स्वीकार की गई त्वरित समीक्षा की अठारह सिफारिशों में कई महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के असामान्य व्यवहार और उससे जुड़ी साइबर सुरक्षा घटनाओं की अनिवार्य सूचना देना, स्वतंत्र विशेषज्ञों से तकनीकी प्रणालियों का मूल्यांकन कराना, गंभीर जोखिमों की पहचान करना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कंपनियों को अपने सुरक्षा मानकों के बारे में पारदर्शिता रखनी होगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कंपनी तकनीकी विकास की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से बच न सके। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रस्तावित कानून अगले वर्ष संसद में प्रस्तुत किए जाने की योजना है। यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने आप में न तो अच्छी है और न बुरी। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग किस उद्देश्य से और किस प्रकार किया जा रहा है। यदि इसका उपयोग चिकित्सा अनुसंधान में हो तो यह गंभीर बीमारियों की पहचान और उपचार में सहायता कर सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में यह विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुरूप अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है। कृषि में मौसम, मिट्टी और फसल संबंधी जानकारी के विश्लेषण से किसानों को लाभ पहुँचा सकती है। सरकारी सेवाओं में इसका उपयोग नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने में सहायक हो सकता है। लेकिन यही तकनीक यदि गलत हाथों में पहुँच जाए तो व्यक्तिगत जानकारी चुराने, झूठी सूचनाएँ फैलाने, आर्थिक धोखाधड़ी करने और सामाजिक तनाव बढ़ाने का माध्यम भी बन सकती है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से किसी व्यक्ति की आवाज की नकल करना, उसके चेहरे का कृत्रिम चित्र बनाना और ऐसी घटनाओं का दृश्य तैयार करना संभव हो गया है, जो वास्तव में कभी हुई ही नहीं। इससे समाज में भ्रम, अविश्वास और धोखाधड़ी की आशंका बढ़ रही है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से झूठा संदेश प्रसारित करना, किसी नागरिक की छवि खराब करना अथवा चुनाव के समय मतदाताओं को भ्रमित करना अब पहले की तुलना में कहीं आसान हो गया है। यदि इन गतिविधियों पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक संबंधों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी एक अन्य बड़ी चिंता व्यक्तिगत निजता की है। आज नागरिकों की बहुत सारी जानकारी विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं के पास उपलब्ध है। स्वास्थ्य, बैंकिंग, शिक्षा, पहचान और पारिवारिक जीवन से संबंधित विवरण अत्यंत संवेदनशील होते हैं। यदि इनका उपयोग बिना अनुमति किया जाए या ये गलत हाथों में पहुँच जाएँ तो व्यक्ति को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए तकनीकी कंपनियों के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वे नागरिकों की जानकारी का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुसार ही करें। साथ ही किसी भी सुरक्षा चूक की स्थिति में प्रभावित लोगों को समय पर सूचना दी जाए और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। ऑस्ट्रेलिया की पहल भारत जैसे विकासशील और विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देती है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सरकारी सेवाओं, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योगों में तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल भुगतान, नागरिक सेवाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं में तकनीक की भूमिका लगातार विस्तृत हो रही है। ऐसे में नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा और तकनीकी प्रणालियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। भारत को भी ऐसी प्रभावी व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है, जिसमें तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन मिले, लेकिन उसके नाम पर नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा से समझौता न हो। कंपनियों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियाँ निर्धारित हों और नियमों का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जा सके। हालाँकि कठोर नियम बनाते समय यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि अत्यधिक नियंत्रण से अनुसंधान और नवाचार की गति प्रभावित न हो। छोटी कंपनियों, नए अनुसंधानकर्ताओं और नवाचार से जुड़े युवाओं के लिए ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए, जिनका पालन करना व्यावहारिक हो। सुरक्षा मानकों का निर्धारण जोखिम के स्तर के अनुसार किया जाना चाहिए। जिस तकनीक का उपयोग सामान्य कार्यों में हो रहा है, उस पर वही कठोरता लागू करना उचित नहीं होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य अथवा नागरिकों की निजी जानकारी से जुड़े अत्यंत संवेदनशील कार्यों में आवश्यक है। सरकार, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग जगत और नागरिक समाज के बीच संवाद भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के साथ मानवीय विवेक और नियंत्रण कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मशीनें कितनी भी सक्षम क्यों न हो जाएँ, उन्हें मानव हितों के अधीन रहना चाहिए। तकनीक का उद्देश्य मनुष्य की क्षमता बढ़ाना है, न कि उसे अपने ही बनाए तंत्र पर निर्भर और असहाय बना देना। यदि कोई प्रणाली गलत निर्णय लेती है तो उसके सुधार की जिम्मेदारी मनुष्य और उसे विकसित करने वाली संस्था की ही होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का यह कदम दुनिया को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि तकनीकी प्रगति केवल तेज गति से नई मशीनें और प्रणालियाँ विकसित करने का नाम नहीं है। वास्तविक प्रगति तभी सार्थक है, जब उसके साथ सुरक्षा, पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने वाले समय में मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बनने जा रही है। इसलिए उसके लाभों को अपनाने के साथ संभावित खतरों के प्रति सजग रहना भी आवश्यक है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें तकनीक मनुष्य की सहयोगी बने, उसकी स्वतंत्रता और निजता के लिए खतरा नहीं। आखिरकार मशीनें मनुष्य के लिए बनाई गई हैं, मनुष्य मशीनों के लिए नहीं। यही विचार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित और मानवीय भविष्य का सबसे मजबूत आधार बन सकता है।

प्रतिबंध नहीं, सुरक्षित डिजिटल संसार की जरूरत

-डॉ. प्रियंका सौरभ-

इक्कीसवीं सदी में इंटरनेट केवल मनोरंजन या संवाद का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि शिक्षा, सूचना, अभिव्यक्ति और सामाजिक सहभागिता का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। विशेषकर बच्चों के लिए डिजिटल दुनिया ज्ञान के नए द्वार खोलती है। ऐसे समय में बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह वंचित करना उनके विकास के अवसरों को सीमित करने जैसा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों की इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार से जुड़े अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के नाम पर व्यापक और एकमुश्त प्रतिबंध उचित समाधान नहीं हो सकते। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापक व्याख्या में डिजिटल पहुँच का महत्व भी सामने आता है। हालांकि, इस अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के इंटरनेट की खुली छूट दे दी जाए।

बच्चों के शैक्षणिक विकास में इंटरनेट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज डिजिटल पुस्तकालय, ऑनलाइन कक्षाएँ, शैक्षणिक वीडियो, आभासी प्रयोगशालाएँ और विभिन्न शिक्षण मंच पारंपरिक शिक्षा के पूरक बन चुके हैं। केंद्र सरकार के दीक्षा मंच और पीएम ई-विद्या जैसी पहल ने डिजिटल शिक्षा को व्यापक बनाने में योगदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए इंटरनेट गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री तक पहुँच का माध्यम बन सकता है। जिन विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक, पुस्तकालय या अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ डिजिटल माध्यम शिक्षा की कमियों को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं।

इंटरनेट बच्चों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उनकी रचनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन को भी प्रोत्साहित करता है। वे विज्ञान, साहित्य, इतिहास, पर्यावरण, कला और तकनीक जैसे विषयों पर अपनी रुचि के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कविताएँ, कहानियाँ, चित्र और विचार साझा कर सकते हैं। इससे उनमें अभिव्यक्ति का आत्मविश्वास और संवाद की क्षमता विकसित होती है। सूचना का अधिकार भी इंटरनेट के माध्यम से अधिक प्रभावी बनता है। बच्चे अपने आसपास की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को समझकर जागरूक नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

डिजिटल पहुँच समावेशी शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। दिव्यांग बच्चों के लिए स्क्रीन रीडर, ऑडियो पुस्तकें, सांकेतिक भाषा आधारित सामग्री और अन्य सहायक तकनीकें शिक्षा को अधिक सुलभ बनाती हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को भी देश-दुनिया के शैक्षणिक संसाधनों से जुड़ने का अवसर



मिलता है। इंटरनेट डिजिटल साक्षरता विकसित करता है, जो भविष्य के रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल बन चुकी है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन शोध, डिजिटल संचार और तकनीकी नवाचार के दौर में बच्चों को डिजिटल दुनिया से दूर रखना उनके भविष्य की संभावनाओं को कमजोर कर सकता है।

हालाँकि, इंटरनेट के लाभों के साथ गंभीर चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा आज अभिभावकों, शिक्षकों, सरकार और डिजिटल मंचों के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन यौन शोषण, बच्चों को बहला-फुसलाकर अनुचित गतिविधियों में शामिल करना, साइबर बुलिंग, अश्लील सामग्री, फर्जी पहचान और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी घटनाएँ बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। कई बार बच्चे अनजान व्यक्तियों से संपर्क में आ जाते हैं और अपनी निजी जानकारी, तस्वीरें या स्थान संबंधी विवरण साझा कर देते हैं। इसका दुरुपयोग उनके मानसिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

साइबर बुलिंग भी एक गंभीर समस्या है। सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियाँ, धमकियाँ, मजाक उड़ाना और निजी तस्वीरों का दुरुपयोग बच्चों के आत्मविश्वास तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल मंचों द्वारा बच्चों के व्यवहार, पसंद और व्यक्तिगत जानकारी का अत्यधिक संग्रह उनकी निजता के अधिकार के लिए चुनौती है। एल्गोरिदम आधारित सामग्री बच्चों को लगातार स्क्रीन पर बनाए रखने का प्रयास करती है, जिससे उनकी पढ़ाई, नींद, शारीरिक गतिविधियों और सामाजिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इसलिए समाधान इंटरनेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में नहीं, बल्कि सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण तैयार करने में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का मूल संदेश भी यही है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले उपाय तर्कसंगत, आनुपातिक और उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए। किसी विशेष खतरे के समाधान के नाम पर सभी बच्चों की इंटरनेट पहुँच समाप्त कर देना उचित नहीं है। प्रतिबंधों के बजाय जोखिम के अनुसार सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए।

सबसे पहले, डिजिटल मंचों को बच्चों के अनुकूल बनाया जाना आवश्यक है। बच्चों के खातों में निजता संबंधी व्यवस्थाएँ पहले से सुरक्षित होनी चाहिए। अनजान व्यक्तियों के संदेशों, अनुचित संपर्कों और संवेदनशील सामग्री तक पहुँच को सीमित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के व्यक्तिगत आँकड़ों का अनावश्यक संग्रह और व्यावसायिक उपयोग रोका जाना चाहिए। आयु के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने और हानिकारक सामग्री की पहचान करने के लिए प्रभावी तकनीकी व्यवस्थाएँ विकसित करनी चाहिए।

दूसरा, अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों पर केवल निगरानी रखने के बजाय उनके साथ विश्वास और संवाद का संबंध विकसित करना होगा। उन्हें समझाना होगा कि इंटरनेट पर प्रत्येक व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होता और निजी जानकारी साझा करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। अभिभावकीय सहमति, आयु के अनुरूप नियंत्रण और समय-समय पर संवाद के माध्यम से बच्चों को जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार सिखाया जा सकता है। बच्चों की निजता और स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए मार्गदर्शन देना आवश्यक है।

तीसरा, डिजिटल सुरक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) के माध्यम से साइबर सुरक्षा, डिजिटल शिष्टाचार, ऑनलाइन धोखाधड़ी, निजता और सूचना की सत्यता से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। बच्चों को यह भी सिखाना होगा कि इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक जानकारी सही नहीं होती। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अनुचित संपर्क की स्थिति में उन्हें बिना भय के अभिभावकों और शिक्षकों को बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

चौथा, डिजिटल मंचों की जवाबदेही सुनिश्चित करना अनिवार्य है। बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री की पहचान, उसे हटाने और संबंधित एजेंसियों तक सूचना पहुँचाने के लिए प्रभावी तंत्र होना चाहिए। साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया सरल और बच्चों के अनुकूल बनाई जानी चाहिए। बाल हेल्पलाइन 1098 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल जैसी व्यवस्थाओं के बारे में बच्चों तथा अभिभावकों को जागरूक करना चाहिए। पुलिस, विद्यालयों और बाल संरक्षण संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है।

अंततः, बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना उनके भविष्य को सुरक्षित करने का स्थायी उपाय नहीं है। उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने योग्य बनाना ही वास्तविक बाल संरक्षण है। अधिकार और सुरक्षा एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए। जिस प्रकार सड़क सुरक्षा के लिए यातायात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, बल्कि नियम, संकेत और सावधानियाँ अपनाई जाती हैं, उसी प्रकार डिजिटल दुनिया में भी सुरक्षा के संतुलित उपाय आवश्यक हैं।

बच्चों के हाथों से इंटरनेट छीनने के बजाय उनके हाथों में डिजिटल विवेक देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रतिबंध भय पैदा कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा, जागरूकता और जवाबदेही ही सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकती है।

(लेखिका पीएचडी (राजनीति विज्ञान), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक हैं)

उत्तर प्रदेश 2027: सत्ता की परीक्षा, समीकरणों की अग्निपरीक्षा

-ललित गर्ग-

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी कई महीने दूर है, लेकिन सत्ता की बिसात बिछ चुकी है। 403 विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला निर्णायक राजनीतिक रणक्षेत्र है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता, भाजपा संगठन में बदलाव, अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति, विपक्षी दलों के संभावित गठजोड़ और मुस्लिम मतदाताओं को लेकर बन रहे नए समीकरण-सभी पर देश की निगाहें टिकी हैं। प्रश्न है कि योगी की मजबूत पकड़ के सामने विपक्ष की चुनौती, मुस्लिम मतों से आगे हिंदू मतदाताओं की बदलती मनोदशा निर्णायक बन पायेगी? प्रश्न यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चेहरा एवं योजनाएं भी क्या प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व एवं भाग्य रचने में सहायक होगी? सबसे पहले भाजपा की स्थिति को देखें तो उसके सामने सबसे बड़ी ताकत योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व और सरकार की उपलब्धियों का दावा है। कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेस-वे, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास तथा केंद्र-राज्य की योजनाओं को भाजपा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। योगी का दावा है कि 2027 का मुकाबला '80 बनाम 20' के रूप में होगा और भाजपा गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतेगा। लेकिन चुनावी राजनीति में दावे और वास्तविक जनभावना के बीच अंतर होता है। इसलिए भाजपा के लिए चुनौती केवल अपनी उपलब्धियां गिनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि सत्ता-विरोधी भावना उसके पारंपरिक सामाजिक आधार में सेंध न लगाए।

भाजपा की रणनीति में इस बार मुस्लिम समाज के भीतर पहुंच बनाने का प्रयास भी स्पष्ट दिखाई देता है। अगस्त 2026 में पार्टी की राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के दो मुस्लिम नेताओं-पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे 2027 से पहले भाजपा की पसमांदा तथा मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति से जोड़ा है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19.26 प्रतिशत थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य क्षेत्रों में उनका चुनावी प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है। लेकिन भाजपा के लिए चुनौती यह है कि मुस्लिम मतों में सेंध लगाना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन अपने हिंदू सामाजिक आधार को एकजुट बनाए रखना हो सकता है।

यहीं चुनाव का दूसरा और शायद अधिक महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। मुस्लिम मतों के ध्रूवीकरण की चर्चा के साथ हिंदू मतदाताओं के भीतर बदलती प्राथमिकताओं को भी समझना होगा। मतदाता केवल जाति और धर्म के आधार पर मतदान नहीं करता। रोजगार, महंगाई, किसान, शिक्षा, युवाओं के अवसर, स्थानीय विधायक की छवि, प्रशासनिक व्यवहार और विकास की वास्तविक पहुंच भी चुनावी निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसलिए 2027 का चुनाव केवल '80 बनाम 20' के राजनीतिक आख्यान से समझना शायद पर्याप्त नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा अवसर यही है। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में बने सामाजिक समीकरणों को विधानसभा स्तर तक मजबूत करना चाहेंगे। पीडीए-पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला भाजपा के गैर-यादव पिछड़े और दलित मतदाताओं में सेंध लगाने की कोशिश करेगा। सपा के सामने चुनौती यह है कि वह अपने सामाजिक समीकरण को केवल चुनावी नारा न रहने दे, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन और उम्मीदवार चयन के माध्यम से उसे वास्तविक राजनीतिक शक्ति में बदल सके। बसपा की भूमिका को भी नजरअंदाज करना भाजपा और सपा दोनों के लिए जोखिम भरा होगा। यदि मायावती दलित मतदाताओं के अपने पुराने आधार को पर्याप्त रूप से सक्रिय कर पाती हैं, तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला परिणाम बदल सकता है। कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देती है, लेकिन यदि वह सपा के साथ तालमेल बनाकर लड़ती है तो विपक्षी मतों के बिखराव को कुछ हद तक रोक सकती है। लेकिन यहां पूर्व के अनुभवों के आधार पर सपा कांग्रेस से तालमेल करने से पहले फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है। भाजपा के सामने दूसरी चुनौती अपने गठबंधन और सामाजिक समीकरणों को संतुलित रखने की है। निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) तथा अन्य सहयोगी दलों की अपेक्षाएं, टिकट वितरण और क्षेत्रीय नेतृत्व की महत्वाकांक्षाएं चुनाव के समय महत्वपूर्ण हो सकती हैं। भाजपा का मजबूत संगठन इन मतभेदों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन टिकट वितरण में छोटी-सी चूक भी कुछ क्षेत्रों में बड़े राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती है। अमित शाह की सक्रियता भी इस चुनाव की गंभीरता को रेखांकित करती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की रणनीति केवल लखनऊ से नहीं, बल्कि दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी में तैयार होने की संभावना है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की अपनी लोकप्रियता और प्रशासनिक छवि भाजपा के लिए सबसे बड़ा स्थानीय चुनावी चेहरा है। इसलिए वास्तविक चुनौती यह होगी कि योगी का नेतृत्व और केंद्रीय संगठनात्मक रणनीति कितनी प्रभावी तरह से एक-दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हैं। इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही होगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश का मतदाता क्या चुनता है-स्थिरता और निरंतरता या परिवर्तन की आकांक्षा। भाजपा के पास संगठन, सत्ता, योगी का चेहरा और व्यापक चुनावी मशीनरी है। विपक्ष के पास सत्ता-विरोधी भावना, सामाजिक न्याय का मुद्दा और भाजपा के खिलाफ विभिन्न वर्गों को एकजुट करने की संभावना है। इसलिए अभी किसी एक दल की जीत को निश्चित मानना जल्दबाजी होगी। भाजपा के लिए 300 पार का लक्ष्य आसान नहीं होगा, लेकिन उसे कमजोर समझना भी विपक्ष की भूल होगी। सपा के सामने अवसर बड़ा है, लेकिन उसे अवसर को जीत में बदलने के लिए सामाजिक समीकरण के साथ संगठनात्मक मजबूती भी दिखानी होगी। बसपा और कांग्रेस की भूमिका कई सीटों पर 'गेम चेंजर' बन सकती है। योगी आदित्यनाथ के सामने 2027 का चुनाव केवल विपक्षी दलों

सार समचार

नाम बदलने, पोर्टलबाजी और घोषणाओं से नहीं, परियोजनाएं पूरी करने से होगा देश का विकास : कुमारी सैलजा

अनप्लग इंडिया

सिरसा। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी एवं कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य कुमारी सैलजा ने केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में आरंभ की गई विकास योजनाओं के नाम और स्वरूप बदलकर उन्हें नई उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करने की राजनीति से देश का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार की परियोजना निगरानी संबंधी अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट पर आधारित प्रकाशित समाचार के अनुसार 1,853 बड़ी परियोजनाओं की लागत में लगभग 3.22 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें 25 मेगा परियोजनाओं की लागत ही करीब 2.11 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है। यह स्थिति सरकारी निगरानी, समयबद्ध क्रियान्वयन और वित्तीय जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के बाद भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को बड़े प्रचार के साथ प्रस्तुत किया। लेकिन भारी धनराशि खर्च होने के बावजूद अनेक शहरों में बुनियादी समस्याएं बनी हुई हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं पूरी हुईं, कितना धन खर्च हुआ और नागरिकों को वास्तविक लाभ कितना मिला।

कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि हरियाणा में पिछले लगभग 12 वर्षों से अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री लगातार नई घोषणाएं करते हैं, लेकिन अनेक घोषणाओं का धरातल पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं देता। सड़कों, पेयजल, सीवरेज, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं में देरी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है।

सांसद ने कहा कि कांग्रेस की नीति पारदर्शी प्रशासन, जनकल्याण और जवाबदेह विकास की रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार को लंबित परियोजनाओं की स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करना चाहिए तथा देरी और लागत वृद्धि के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

एक-एक पाई का हिसाब देना सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व

कुमारी सैलजा ने कहा कि जनता को नए पोर्टल, बदले हुए नाम और आकर्षक नारों की नहीं, समय पर पूरी होने वाली विकास परियोजनाओं की आवश्यकता है। सार्वजनिक धन की एक-एक पाई का हिसाब देना सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है।

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में फिर हड़ताल पर जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। हरियाणा में नर्सिंग ऑफिसर्स ने ऑनलाइन मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में एक बार फिर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य प्रधान विनीता बांगड़ ने बुधवार को कहा कि सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ धोखा किया है। बिना सूचित किए ट्रांसफर का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। अब सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।

विनीता बांगड़ ने कहा कि ऑनलाइन मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में नर्सिंग ऑफिसर्स ने पांच-छह अक्टूबर 2026 को हड़ताल की थी। उस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डा. सुमिता मिश्रा ने आश्वासन दिया था कि वे मुख्यमंत्री के समक्ष नर्सिंग ऑफिसर्स पर यह पॉलिसी लागू नहीं करने की सिफारिश करेंगी। इस आश्वासन पर उन्होंने हड़ताल को समाप्त करवाया था। विनीता बांगड़ ने कहा कि इसके बाद इस पर क्या निर्णय हुआ, क्या चर्चा हुई, इसकी कोई जानकारी नर्सिंग एसोसिएशन को नहीं दी गई। अब अचानक बिना सूचित किए ट्रांसफर के आदेश निकाले जा रहे हैं। यह नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ सरासर धोखा है। अब अनिश्चिकालीन हड़ताल होगी। क्योंकि जबरन ट्रांसफर पॉलिसी थोपकर सरकार नर्सिंग ऑफिसर्स को अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया है। जल्द ही हड़ताल की तारीख तय की जाएगी। हड़ताल में जान-माल के नुकसान की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने सभी नर्सिंग ऑफिसर्स से एकजुट होकर आंदोलन में भाग लेने की अपील की है।

14 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में होंगी बैठकें

विनीता बांगड़ ने बताया कि हरियाणा के सभी जिलों के नर्सिंग एसोसिएशन प्रधान अपने-अपने जिलों में 14 नवंबर 2026 तक मीटिंग रखेंगे। अपने-अपने जिलों में चर्चा करेंगे, ताकि आंदोलन की तैयारी की जा सके। सभी जिलों से सुझाव लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को बंद करवाना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और स्पेशल टास्क फोर्स की गाइडलाइन को लागू करवाना है। ऐसे में अब हड़ताल का कदम फिर से उठाना होगा।

नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी आम कर्मचारियों से अलग

विनीता बांगड़ ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, रात में परिवहन की सुविधा का ख्याल नहीं रख रही। नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी आम कर्मचारियों यानी अन्य विभागों के कर्मचारियों से बिल्कुल अलग है। हमारी कोई 9 से 5 बजे की ड्यूटी नहीं है। सुबह, दोपहर, रात का ड्यूटी शेड्यूल रहता है। हम 24 घंटे की सेवा देते हैं। इसलिए सरकार आवासीय सुविधा दे। बच्चों की एडमिशन फीस सरकार वहन करे, जो तबादला होने पर दूसरे जिलों में देनी पड़ेगी। केंद्र के समान नर्सिंग अलाउंस दिया जाए।

नर्सिंग ऑफिसर्स की ट्रांसफर से परिवार होंगें प्रभावित

सबसे बड़ी परेशानी नर्सिंग ऑफिसर्स का परिवार और सुरक्षा है। किसी के बच्चे बिल्कुल छोटे हैं तो किसी के स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। किसी के जवान बच्चे हैं। ऐसे में अचानक दूसरे जिले में ट्रांसफर कर देना पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। साथ ही नर्सिंग ऑफिसर्स की अपनी सुरक्षा का भी सवाल है। रात को ड्यूटी पर जाते हुए और रात 8 बजे खत्म होने वाली शाम की शिफ्ट में ओवर देकर आना पड़ता है। अगर कोई मरीज सीरियल हो तो ड्यूटी से निकलते हुए 9 भी बज सकते हैं। महिला स्टाफ का ऐसी परिस्थिति में अकेले आना-जाना कितना खतरनाक है, इसका सरकार को अंदाजा नहीं है। राज्य प्रधान ने कहा कि जबरन ट्रांसफर पॉलिसी थोपकर सरकार नर्सिंग ऑफिसर्स को अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसा फैसला लेने पर मजबूर कर रही है। जल्द ही हड़ताल की तारीख तय की जाएगी। हड़ताल में जान-माल के नुकसान की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने सभी नर्सिंग ऑफिसर्स से एकजुट होकर आंदोलन में भाग लेने की अपील की है।

जांच में दोषी मोहित शर्मा पर निगमायुक्त रहे मेहरबान, डीसी के आदेश से भी नहीं हटाया

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। सदर बाजार से एक दुकानदार का अवैध रूप से सामान उठाने के मामले की जांच में दोषी ठहराए जाने के साथ उसे तुरंत प्रभाव से ड्यूटी से निष्कासित करने के आदेशों की धज्जियां गुरुग्राम नगर निगम में उड़ाई गई है। नगराधीश (सीटीएम) के द्वारा जांच और उपायुक्त के आदेशों के बाद भी उस पर नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने कोई संज्ञान नहीं लिया। निगमायुक्त द्वारा उसे निष्कासित किया जाना था, मगर ऐसा करने की बजाय उसे शो कॉज नोटिस देकर जवाब मांगा गया। निगमायुक्त की यह कार्यप्रणाली सवाल खड़े करती है कि आखिर क्यों ऐसे व्यक्ति का बचाव किया गया, जो जांच में दोषी सिद्ध हो चुका है।

नगर निगम गुरुग्राम की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के सदस्य मोहित शर्मा द्वारा सदर बाजार स्थित जैन जलेबी दुकान के सामने स्थित जिनेंद्र जैन नामक व्यक्ति की दुकान से अवैध कब्जा बताकर सामान उठाया गया था। पीड़ित दुकानदार जैनेंद्र जैन ने मोहित शर्मा द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर जिला उपायुक्त के समक्ष शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। जिला उपायुक्त के निर्देशों पर नगराधीश (सीटीएम) ने इस मामले की गहनता से जांच की। 25 अप्रैल 2024 को नगराधीश द्वारा सौंपी गई जांच में कहा गया कि मोहित शर्मा द्वारा दुकानदार जैनेंद्र जैन का सामान उठाया जाना सही नहीं बल्कि अवैध कार्य था। साथ ही जांच में यह भी लिखा गया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा मोहित शर्मा को ऐसी चेकिंग के लिए मनोनीत किया गया है।

नायब सिंह सैनी का बड़ा निर्देश: एससी-एसटी मामलों में 60 दिन में दाखिल करनी होगी चार्जशीट, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एससी-एसटी वर्ग के नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़े प्रत्येक मामले में 60 दिनों के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा। सभी मामलों में इस समय-सीमा का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम-1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे।

एससी-एसटी मामलों में 28 प्रतिशत की कमी

बैठक में पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में एससी-एसटी से संबंधित मामलों में लगभग



28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने पर 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जिला एवं उपमंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मामलों की जांच, प्रगति और समयबद्ध निपटान की निगरानी करेंगे।

पांच जिलों में स्थापित होंगी स्पेशल कोर्ट

एससी-एसटी से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में स्पेशल न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन न्यायालयों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़े।

अधिक मामले वाले जिलों और थानों पर रहेगी नजर

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में एससी-एसटी से जुड़े अपराधों की संख्या अधिक है, वहां विशेष अभियान चलाकर विस्तृत समीक्षा की जाए। अपराधों के कारणों की पहचान कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

उन्होंने अधिक मामले दर्ज होने वाले पुलिस थानों की अलग से पहचान कर वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष निगरानी की जिम्मेदारी देने को कहा। लंबे समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पंचायतों में पिछले दो वर्षों के दौरान इस श्रेणी का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए पंचायत विभाग ऐसी पंचायतों की सूची तैयार कर सरकार को भेजे।

1,046 पीड़ितों को 13.49 करोड़ रुपये की सहायता

बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक अत्याचार से पीड़ित 1,046 व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास के लिए 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

वहीं, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने इसे सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाली सराहनीय पहल बताया।

इसके अलावा अत्याचार निवारण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और महाविद्यालयों में भाषण, लेखन एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के साथ सेमिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय, समानता और प्रत्येक नागरिक की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा, ताकि किसी भी पीड़ित को न्याय पाने के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। उन्होंने जिला एवं उपमंडल स्तर पर निर्धारित समय के अनुसार नियमित बैठकें आयोजित करने और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में विधायक डॉ. कृष्ण कुमार, भगवानदास कबीरपंथी, जरनैल सिंह, शीशपाल केहरवाला, पवन खरखौदा, बिमला चौधरी, कपूर सिंह वाल्मीकि, बंतो कटारिया सहित गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं समिति के सदस्य मौजूद रहे।

सोनीपत में बदमाशों ने आउटलेट मैनेजर की गोली मारकर की हत्या

अनप्लग इंडिया

सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में एक रोडरेज की घटना में आउटलेट मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, प्रह्लाद नाम का व्यक्ति कैथल स्थित डे-बैक आउटलेट में मैनेजर था। बताया गया कि जम्मू-कटरा हाईवे पर खेड़ा खेड़ी गांव के पास बदमाशों ने पहले मैनेजर की गाड़ी को टक्कर मारी थी। गाड़ी रुकवाकर जब प्रह्लाद ने टक्कर मारने का कारण पूछा और विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची बरोदा थाने की पुलिस टीम ने गंभीर हालत में प्रह्लाद को रोहतक पीजीआई के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इससे पहले, शनिवार को हरियाणा के फरीदाबाद में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक



व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक, परमजीत धनखड़ मूल रूप से हिसार के रहने वाले थे। वह सेक्टर-21सी स्थित मकान नंबर 641 की पहली मंजिल पर पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहते थे। वह एक बड़ी राष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत थे और नौकरी के सिलसिले में सिंगापुर में रह रहे थे। दो दिन पहले ही वह अपने परिवार के पास लौटे थे। 24 नवंबर को उनके भांजे की शादी होनी है। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं लेकिन इस घटना ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया।

बताया गया कि वारदात वाली रात आठ बजे परमजीत जिम से घर लौटे थे। इसी दौरान पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर उनकी तीसरी मंजिल पर रहने वाले पड़ोसी मोहन उर्फ मोनू शर्मा से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर मोनू ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली और परमजीत पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल परमजीत की मौत हो गई।

हरियाणा में खुलेंगी 2,651 फेयर प्राइस शॉप्स, इच्छुक आवेदक 25 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गरीब और पात्र परिवारों के लिए राशन डिपो की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए राज्यभर में 2,651 उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। हाल ही में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश में खाली पड़ी 2,651 उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राइस शॉप्स) के लिए लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब इच्छुक आवेदक 25 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकतें हैं, जबकि पहले इसकी अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026 निर्धारित थी।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से विशेष रूप से उन दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा, जहां मौजूदा डिपो काफी दूर स्थित हैं। इस योजना से न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होगी, बल्कि युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण को भी एक नया बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा 10 अक्टूबर 2026 को की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि योग्य आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 25 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन से जुड़े विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता शर्तें और निर्देश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https//haryanafood.gov.in पर उपलब्ध हैं।



प्रवक्ता ने यह भी बताया कि रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का जिला-वार और गांव-वार विवरण भी विभाग की वेबसाइट और संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइटों पर देखा जा सकता है। विभाग ने सभी योग्य युवाओं और महिलाओं से इस बढ़े हुए अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है और सलाह दी है कि निर्धारित अंतिम तिथि से पहले सरल पोर्टल पर आवेदन अवश्य जमा कर दें। इस पहल से हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मजबूत होने और जमीनी स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

हरियाणा में 12 नवंबर से कांग्रेस का 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान, संजय दत्त और राव नरेंद्र सिंह करेंगे प्रदेशव्यापी दौरा

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा में चुनावी पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी अभियान शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत हरियाणा कांग्रेस 12 नवंबर से 24 नवंबर 2026 तक प्रदेशभर में 'वोट बचाओ-देश बचाओ' चौपाल अभियान चलाएगी। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता विभिन्न जिलों का दौरा कर चौपालों के माध्यम से आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह दो सप्ताह तक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अभियान के जरिए लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, चुनावी निष्पक्षता और मतदाताओं के अधिकारों को लेकर जनजागरण किया जाएगा। 2024 के विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा पर लगाए आरोप

कांग्रेस ने इस अभियान को हरियाणा के 2024 विधानसभा चुनावों की निष्पक्षता से जुड़े अपने आरोपों से भी जोड़ा है। पार्टी का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में उसके पक्ष में आए जनादेश को कथित चुनावी हेराफेरी और वोट चोरी के जरिए पलटा गया तथा इसका फायदा भाजपा को मिला।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मतदाता सूचियों में संदिग्ध प्रविष्टियों, डुप्लीकेट मतदाताओं और संदेहास्पद पतों को लेकर उठाए गए सवालों का भी अभियान में मुद्दा बनाया जाएगा। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।

SIR पर रोक और वोट चोरी की जांच की मांग

कांग्रेस इस अभियान के दौरान अपनी प्रमुख मांगों को जनता के बीच रखेगी। इनमें विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर रोक लगाने, कथित वोट चोरी के आरोपों की स्वतंत्र एवं पारदर्शी जांच



कराने और मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग शामिल है।

इसके अलावा पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ आपराधिक जांच की मांग भी दोहराएगी। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए।

हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला समेत पूरा नेतृत्व होगा सक्रिय

इस प्रदेशव्यापी अभियान में हरियाणा कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व भी सक्रिय भागीदारी करेगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एआईसीसी महासचिव कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, सीडब्ल्यूसी के स्थायी आमंत्रित सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा तथा पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी बीरेंद्र सिंह, धर्मपाल मलिक, अशोक तंवर और उदयभान भी चौपालों में शामिल होंगे।

इसके अलावा पार्टी के सांसद, विधायक, जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और विभिन्न अग्रिम संगठनों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी अभियान का हिस्सा बनेंगे।

गांव-गांव तक पहुंचाएंगे लोकतंत्र बचाने का संदेश-कांग्रेस के अनुसार, 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक जिले, ब्लॉक, गांव और घर तक मताधिकार की सुरक्षा का संदेश पहुंचाना है। चौपालों के माध्यम से लोगों को मतदाता सूची में संभावित अनियमितताओं के प्रति जागरूक किया जाएगा और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनभागीदारी बढ़ाई जाएगी।

पार्टी का कहना है कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। इसकी सुरक्षा किसी एक राजनीतिक दल या चुनाव तक सीमित मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने का सवाल है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि चुनावी निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित होने तक यह अभियान जारी रखा जाएगा।

एनआईआरसी हिसार ब्रांच 14 नवंबर को आयोजित करेगी प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनप्लग इंडिया

हिसार : चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था एनआईआरसी हिसार ब्रांच द्वारा 14 नवंबर को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हिसार के सेक्टर 16-17 के इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित आईसीएआई भवन में पियर रिव्यूअर के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। एनआईआरसी हिसार ब्रांच के चेयरमैन सीए अजय गोयल ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पियर रिव्यूअर के लिए काफी लाभकारी व जानकारी से परिपूर्ण रहेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीए आयुष जैन व सीए नकुल अरोड़ा अतिथि वक्ता रहेंगे। चेयरमैन सीए अजय गोयल ने कहा कि एनआईआरसी हिसार ब्रांच आईसीएआई के तत्वावधान में सीए व सीए स्टूडेंट्स के हितों के लिए कार्य कर रही है। इसके साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आर्थिक क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में 14 नवंबर को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एनआईआरसी हिसार ब्रांच के वाइस चेयरमैन सीए विशेष भारद्वाज,



सचिव सीए राजेश सिहाग, कोषाध्यक्ष सीए सुनील गोदारा, एनआईसीएएसए चेयरमैन सीए प्रतीक आर्य, एनआईआरसी हिसार ब्रांच के पूर्व चेयरमैन सीए अमन बंसल, कार्यकारी सदस्य सीए मुकुल मित्तल एवं एक्स ऑफिशियो सदस्य सीए अजीत सिंह चंदेल सहित तमाम पदाधिकारियों की विशेष भूमिका रहेगी।

रेलवे रोड पर लापरवाही व कथित भ्रष्टाचार पर भी एक्शन लो सीएम साहब: पंकज डावर

अनप्लग इंडिया

गुडग़ांव। कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने बुधवार को ओल्ड रेलवे रोड के डिवाइडर की दुर्दशा दिखाते हुए भाजपा सरकार, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकारी काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार देखना है तो ओल्ड रेलवे रोड पर जाकर देख लीजिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि रेलवे रोड पर हुए इस घटिया काम की जांच कराकर दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज की जाए। हकीकत तो यह है कि यह काम हुआ ही नहीं।

पंकज डावर ने कहा कि कबीर भवन चौक से आगे रेलवे रोड तक डिवाइडर पर करीब पांच महीने पहले लॉकिंग टाइलें लगाई गई थीं। काम इतना घटिया था कि कोई भी देखकर बता दे कि इसमें बड़ी लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार न हुआ होता तो यह काम बहुत बढ़िया हो जाता। ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत इसमें दिख रही है। पहली बार जब यह



डिवाइडर पर टाइलें लगाई गई तो ना टाइलों के लॉक मिलाए गए, ना लेवल सही किया गया। टाइलें बेतरतीब तरीके से, काफी गैप छोड़कर, ऊबड़-खाबड़ लगा दी गईं।

डावर ने कहा कि उन्होंने 9 जुलाई 2026 को इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। आवाज उठाने के अगले ही दिन ठेकेदार ने टाइलों को दोबारा लगाने के नाम पर उखाड़कर एक जगह इकट्ठा कर दिया। लेकिन आज पांच महीने बीतने के बाद भी टाइलें ज्यों की त्यों पड़ी हैं। उन्हें दोबारा लगाने की शुरुआत तो क्या सोचा तक नहीं हुई है। इकट्ठी की गई टाइलें अब धीरे-धीरे बिखरती जा रही हैं, टूट रही हैं। इसे भ्रष्टाचार ना कहें तो क्या कहें। आखिर गुडग़ांव का प्रशासन, नगर निगम, जीएमडीए क्या कर रहा है। जिस भी विभाग के अंतर्गत यह काम है, उस विभाग के किसी अधिकारी ने क्या कभी यहां आकर काम को देखा या नहीं। जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी यहां खुलेआम की जा रही है। सरकार को इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, ताकि काम तय समय पर पूरे हों और जनता को राहत मिले।

काम की किसी को चिंता नहीं, होनी चाहिए जांच-डावर ने जनप्रतिनिधियों पर भी लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार को किसी का डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ऊपर से नीचे तक कोई पूछने वाला नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यहां से रोजाना भाजपा के नेता, विधायक, पार्षद और अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन किसी को इस डिवाइडर की दुर्दशा नजर नहीं आती। यह बताता है कि भाजपा सरकार विकास के सिर्फ ढोल पीटती है, जमीन पर विकास की हकीकत रेलवे रोड का यह डिवाइडर है। इस डिवाइडर पर बीजेपी नेताओं के घरों का रास्ता बताने वाले बोर्ड तो लगे हैं मगर किसी को डिवाइडर की चिंता नहीं।

जांच हो और दोषियों पर दर्ज हो एफआईआर

डावर ने कहा कि जनता की कमाई को इस तरह बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर सीएम साहब सच में भ्रष्टाचार पर एक्शन लेना चाहते हैं तो रेलवे रोड पर इस लापरवाही पर भी एक्शन लें। इस काम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह जांच होनी चाहिए कि इस काम के बिल पास हुए या नहीं, पेमेंट हुई या नहीं। दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

संक्षिप्त डायरी

दो वर्षों से दो सेक्टरों को मिला यूपी रेरा का पंजीकरण, लंबे समय से चल रहा था प्रयास

अनप्लग इंडिया

बरेली बीडीए ने ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-5 और सेक्टर-8 का यूपी रेरा में पंजीकरण करा लिया है। यह पंजीकरण लगभग दो वर्षों से लंबित था। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्राधिकरण ने ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-5 और सेक्टर-8 का उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में पंजीकरण करा लिया है। यह पंजीकरण लगभग दो वर्षों से लंबित था। प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने बताया कि ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-8 में कुल 216 भूखंड नियोजित हैं। इनमें आवासीय, मिश्रित भू-उपयोग और सार्वजनिक सुविधाओं के भूखंड शामिल हैं। इस परियोजना में पार्क, चौड़ी सड़कें, जलापूर्ति, सीवर, स्ट्रीट लाइट और आधुनिक विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसी तरह, सेक्टर-5 परियोजना के तहत भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय भूखंड जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। सौम्या पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और सुविधायुक्त आवास मिले। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों की मेहनत की कमाई का निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहे। दोनों परियोजनाओं में सभी विकास कार्य उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएंगे। परियोजनाओं से जुड़ी सभी जानकारियां प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। आम निवेशकों और आवंटियों को मिलेंगे विशेष अधिकार बीडीए की परियोजनाओं के यूपी रेरा में पंजीकृत होने से निवेशकों और संपत्ति खरीदने वालों को कई बड़े कानूनी और वित्तीय सुरक्षा कवच मिल गए हैं। रेरा नियमों के तहत अब स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही विकास कार्य कराना, समयबद्ध तरीके से कब्जा देना और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य होगा। इन परियोजनाओं के लिए पूरी तरह पृथक (अलग) बैंक खाते संचालित किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आवंटियों से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग केवल और केवल उसी विशिष्ट परियोजना के विकास में ही किया जाए। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की विवाद या शिकायत की स्थिति में आवंटियों को सीधे यूपी रेरा मंच पर सुनवाई का विधिक अधिकार भी प्राप्त हो गया है।

पेड़ से बाइक सवार पर कूदा बंदर, पलटी बाइक, बड़े पिता और भतीजी की मौत

अनप्लग इंडिया

गाजीपुर गाजीपुर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक बंदर बाइक सवार के ऊपर कूद गया। जिससे अनियंत्रित होकर बाइक पलट गई। हादसे में मासूम बच्ची और उसके बड़े पिता की मौत हो गई। गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना क्षेत्र के मिजार्बाद मनिया गांव के सामने पेड़ से हेलमेट पर बंदर के कूदने से बाइक अनियंत्रित होकर गाजीपुर- भरौली मार्ग पर पलट गई। इधर, पीछे से आ रही कार से कुचलकर मासूम समीक्षा (6 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल बड़े पिता कमलेश कुमार (40) की भी हादसे के दो घंटे बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। बड़े पिता कमलेश भतीजी समीक्षा को बाइक से लेकर घर जा रहे थे। कैसे हुआ हादसा थानाध्यक्ष राजीव पांडेय ने बताया कि बलिया जनपद के नरही थाना के भरौली गांव निवासी विमलेश राम ने तहरीर देकर बताया कि बड़े भाई कमलेश कुमार छह वर्षीय पुत्री समीक्षा को लेकर वीरपुर रिश्तेदारी में गए थे। वहां से वह पुत्री को बाइक से लेकर घर आ रहे थे। मिजार्बाद मनिया गांव के सामने बाइक चला रहे बड़े भाई कमलेश कुमार के हेलमेट पर अचानक पेड़ पर बैठा बंदर कूद गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा। अभी आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक पीछे से आ रहे कार ने बेटी समीक्षा को कुचल दिया, जिससे पुत्री की मौके पर मौत हो गई। वहीं, ग्रामीणों ने घायल बड़े भाई को उपचार मुहम्मदाबाद सीएचसी लाने के साथ ही परिजनों को हादसे की जानकारी दी। परिवार के लोग मुहम्मदाबाद सीएचसी पहुंचे तो डॉक्टरों ने बड़े भाई कमलेश कुमार को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उपचाार के दौरान बड़े भाई की मौत हो गई। थानाध्यक्ष राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। विमलेश राम की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।

जीटी रोड पर दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत, गलत दिशा से ओवरटेक करने में हादसा, एक की मौत और तीन घायल

अनप्लग इंडिया

कानपुर। बिठूर थाना क्षेत्र के नारामऊ में जीटी रोड हाईवे पर गलत दिशा से ओवरटेक करने के दौरान दो बाइकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र अंतर्गत नारामऊ चुंगी जीटी रोड हाईवे के पास गुरुवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गलत दिशा से ओवरटेक करने की कोशिश में तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में दोनों बाइकों पर सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, एक बाइक पर नानकारी निवासी मयंक दुबे, सिंहपुर निवासी शुभम मिश्रा और तन्वी सवार होकर मंधना से आईआईटी गेट की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान नारामऊ की ओर से आईआईटी गेट की तरफ जा रही दूसरी बाइक से उनकी सीधी टक्कर हो गई। ओवरटेक करने की कोशिश में हादसा बताया जा रहा है कि एक बाइक चालक तेजी से गलत दिशा से ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। तभी दोनों बाइकें आपस में बुरी तरह उलझ गईं और सड़क पर गिर पड़ीं। हादसे के बाद राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया। एक की मौत, चार घायलों का उपचार जारी दूसरी बाइक पर सवार कल्याणपुर निवासी रंजीत सोनकर को सीएचसी चौबेपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, उनके साथ मौजूद बैरीअकबरपुर (कल्याणपुर) निवासी साथी सुजीत की गंभीर हालत को देखते हुए रामा अस्पताल मंधना में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवायापहली बाइक पर सवार मयंक दुबे, शुभम मिश्रा और तन्वी को इलाज के लिए कल्याणपुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही बिठूर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

बाइक में पीछे से दूसरी बाइक ने मारी टक्कर, सड़क पर गिरी महिला की मौत

एजेंसी

कानपुर। घाटमपुर के रेउना थाना क्षेत्र में मुगल रोड पर घुघुआ पुल के पास बाइक की टक्कर लगने से महिला सड़क पर गिर गई और सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। महिला पति और तीन साल की बेटी के साथ मायके से ससुराल लौट रही थी। कानपुर के घाटमपुर में रेउना थाना क्षेत्र के घुघुआ पुल के पास मंगलवार की शाम पति के साथ बाइक पर जा रही महिला पीछे से दूसरी बाइक की टक्कर लगने से सड़क पर जा गिरी। गंभीर हालत में उसे सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कार दिया। महिला पति व बेटी के साथ अपने मायके से ससुराल जा रही थी। काटर गांव निवासी फूल सिंह की ससुराल कानपुर देहात के रूरा में है। फूल सिंह ससुराल से अपनी पत्नी कुसुम कली (30) व तीन साल की बेटी को बाइक पर लेकर अपने गांव काटर जा रहे थे। फूल सिंह ने बताया कि जैसे ही मुगल रोड पर घुघुआ पुल के पास पहुंचे तभी उनकी बाइक में पीछे से दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने बताया कि पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में महिला की चलती बाइक से अचानक गिरने से मौत हुई है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बिजली विभाग की टीम बनकर पहुंचे फर्जी युवक, दुकान पर अवैध वसूली और मारपीट, ग्रामीणों ने खदेड़ा

अनप्लग इंडिया

जालौन। जिले के थाना कैलिया क्षेत्र अंतर्गत नरी गांव में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब बिजली विभाग के फर्जी कर्मचारी बनकर आए कुछ अज्ञात युवकों ने एक स्थानीय दुकान पर अवैध वसूली और मारपीट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। अचानक हुई इस घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। सतर्क ग्रामीणों के समय पर हस्तक्षेप करने और कड़ा विरोध जताने के कारण फर्जी चेकिंग दस्ता मौके से गाड़ी छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। पीड़ित दुकानदार ने स्थानीय कैलिया थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या है पूरा मामला प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 10 नवंबर की दोपहर करीब दो बजे की बताई जा रही है। कैलिया क्षेत्र के



ग्राम नरी निवासी शिकायतकर्ता माता प्रसाद हरबान अपनी दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान एक संदिग्ध चार पहिया वाहन (गाड़ी संख्या से कुछ अज्ञात युवक उनकी दुकान के बाहर आकर रुके। गाड़ी से उतरते ही युवकों ने रोब झाड़ते हुए खुद को बिजली विभाग का अधिकृत चेकिंग दस्ता बताया। दुकान में प्रवेश करते ही फर्जी कर्मचारियों ने बिजली कनेक्शन, मीटर और बिल की जांच के नाम पर दुकानदार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। चेकिंग की आड़ में आरोपी कथित रूप से अनधिकृत रूप से अवैध पैसों (वसूली) की मांग करने लगे। विरोध करने पर अभद्रता और मारपीट का प्रयास जब दुकानदार माता प्रसाद ने युवकों के व्यवहार और चेकिंग की प्रामाणिकता पर संदेह जताते हुए उनका विरोध किया तथा उनका पहचान पत्र दिखाने को कहा, तो फर्जी कर्मचारी भड़क गए। आरोपियों ने दुकानदार के साथ सरेआम गाली-गलौज और अभद्रता शुरू कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि फर्जी कर्मचारियों ने दुकानदार के साथ मारपीट करने की कोशिश की और डराने-धमकाने का प्रयास किया। ग्रामीणों की मुस्तैदी से भागे शातिर दुकान पर हो रहे हंगामे और दुकानदार के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण और व्यापारी बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए। जब ग्रामीणों ने युवकों से सख्ती से पूछताछ की और बिजली विभाग से उनके संबंध के बारे में दस्तावेज मांगे, तो आरोपी घबरा गए। ग्रामीणों का आक्रोश और एकजुटता देखकर फर्जी चेकिंग दस्ता खुद को घिरता हुआ महसूस करने लगा। ग्रामीणों के आक्रामक रुख को देखते हुए सभी आरोपी अपनी गाड़ी में सवार होकर मौके से आनन-फानन में भाग निकले। थाना कैलिया में शिकायत दर्ज, पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग घटना के तुरंत बाद पीड़ित दुकानदार माता प्रसाद हरबान ग्रामीणों के साथ थाना कैलिया पहुंचे और पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र दिया। शिकायत पत्र में गाड़ी संख्या का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए अज्ञात आरोपियों की जल्द से जल्द पहचान करने की गुहार लगाई गई है। पीड़ित और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि: वाहन संख्या के आधार पर आरोपियों की तत्काल शिनाख्त की जाए। फर्जी कर्मचारी बनकर ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध वसूली करने वाले इस गिरोह का पदाफाश किया जाए। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, फजीवाड़ा, अवैध वसूली और मारपीट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। क्षेत्र में फैला आक्रोश, बिजली विभाग भी सतर्क इस घटना के बाद से नरी गांव सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के फर्जी गिरोह सक्रिय हो जाते हैं, जो चेकिंग या जुमार्ने का भय दिखाकर भोले-भाले किसानों और छोटे व्यापारियों का शोषण करते हैं। स्थानीय निवासियों ने विद्युत निगम (पावर कॉरपोरेशन) के उच्च अधिकारियों से भी अपील की है कि वे चेकिंग टीमों की पहचान और कार्यशैली को पारदर्शी बनाएं, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व विभागीय कर्मचारी बनकर आम जनता को ठग न सके। फिलहाल, कैलिया थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दर्ज वाहन संख्या के जरिए गाड़ी के मालिक और उसमें सवार युवकों का सुराग लगाया जा रहा है।

ट्रैजरी के चार एकाउंटेंट का बढ़ा रुतबा,असिस्टेंट ट्रेजरी आफसर के ओहदे पर हुआ प्रमोशन



अनप्लग इंडिया) सीनियर ट्रैजरी आफसर अंकिता सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैजरी में तैनात चार एकांउटेंट को असिस्टेंट ट्रैजरी आफसर के ओहदे पर हुआ प्रमोशन। प्रमोशन हासिल करने वालों में प्रेमी प्रजापति, अभिराम तिवारी, पवन कुमार सहित कौशल किशोर मिश्रा खासतौर से हैं शामिल। इस मौके पर सीनियर ट्रैजरी आफसर अंकिता सिंह ने सभी प्रमोटेड असिस्टेंट ट्रेजरी आफसर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि प्रमोशन सिर्फ ओहदे में इजाफा नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के साथ ही दायित्वों में भी वृद्धि की पहचान है। उन्होंने सभी से उम्मीद करते हुये कहा कि वो अपने नये ओहदे की इज्जत और उस्से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुये पूरी ईमानदारी के साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभायें। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में फाइनेंशियल और ट्रैजरी से जुड़े कामों में वख्त के साथ ही ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है।

रेलवे ने 24 ट्रेनों के नंबर बदले, 12 गाड़ियों का बरेली होकर होता है संचालन

अनप्लग इंडिया

बरेली रेलवे ने परिचालनिक सुगमता के लिए 24 ट्रेनों के नंबर बदले हैं। इन बदलावों को एक जनवरी से लागू किया जाएगा। इनमें से 12 ट्रेनों का संचालन बरेली होकर किया जाता है। रादाबाद मंडल के वरिष्ठ डीसीएम महेश यादव ने यह जानकारी दी। रेलवे ने परिचालनिक सुगमता के लिए 24 ट्रेनों के नंबर बदले हैं। इनमें 12 ट्रेनों का संचालन बरेली होकर किया जाता है। एक जनवरी से इन गाड़ियों का नए नंबरों से संचालन किया जाएगा। मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि मुजफ्फरपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस का नंबर 12557-58 से बदलकर 15577-78 हो किया गया है। इसके अलावा अब मुजफ्फरपुर-आनंद विहार गरीब रथ 12211-12 के स्थान पर 14031-32, राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस 13291-92, सहरसा-अमृतसर गरीब



रथ का नंबर 14693-94, दरभंगा-जालंधर एक्सप्रेस का 15541-42 और पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्सप्रेस का 13255-56 नंबर से संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल 24 ट्रेनों के नंबर परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। चंडीगढ़-बरौनी के बीच एक-एक फेरे के लिए विशेष ट्रेन छठ पूजा से पहले पूर्वांचल और बिहार रूट की ट्रेनों पर यात्रियों का लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस बीच रेलवे ने बरौनी-चंडीगढ़ के बीच एक-एक फेरे के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूवो र रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 04538 चंडीगढ़-बरौनी आरक्षित विशेष गाड़ी 10 नवंबर को चंडीगढ़ से रात 10 बजे चलने के बाद अंबाला कैंट, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद होते हुए अगले दिन सुबह 7:44 बजे बरेली आएगी। यहां से चलने के बाद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए तीसरे दिन तड़के 3:30 बजे बरौनी पहुंचेगी। 04537 बरौनी-चंडीगढ़ आरक्षित विशेष गाड़ी 12 नवंबर को बरौनी से सुबह 6:30 बजे चलने के बाद दूसरे दिन सुबह 5:10 बजे बरेली आएगी। दोपहर 1:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। लखनऊ-दिल्ली एसी सुपरफास्ट में अतिरिक्त कोच दिल्ली-लखनऊ रूट पर यात्रियों के दबाव को देखते हुए रेलवे ने लखनऊ-दिल्ली एसी सुपरफास्ट में एसी तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि 12429 लखनऊ-दिल्ली एसी सुपरफास्ट में 11 से 16 और 12430 दिल्ली-लखनऊ एसी सुपरफास्ट में 12 से 17 नवंबर तक एक-एक तृतीय श्रेणी एसी कोच लगाया जाएगा।

बरेली में दो दोस्तों की मौत, एक अन्य की हालत नाजुक

अनप्लग इंडिया

बरेली बरेली के शाही क्षेत्र में मंगलवार रात भीषण हादसा हुआ। शाही-शेरगढ़ रोड पर तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई। उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बरेली जिले में भाई दूज से पहले मंगलवार रात शाही-शेरगढ़ रोड पर हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों एक ही बाइक से बसावनपुर गांव में लगे दिवाली मेले में जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया। शाही थाना क्षेत्र के अमौर गांव निवासी दीपक, मनोज और योगेश दोस्त थे। मंगलवार देर रात तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर बसावनपुर गांव में दिवाली मेला देखने जा रहे थे। बताया गया है कि शाही-शेरगढ़ रोड पर खजुरिया चौराहे हनुमान मंदिर के करीब इनकी बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंभे पर लगा बिजली तार टूटकर जमीन पर गिर गया और तीनों युवक बाइक से उछलकर खाई में जा गिरे। हादसे के समय बाइक दीपक चला रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। राहगीरों की सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में थानाध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। हादसे में गंभीर रूप से घायल दीपक (24 वर्ष) और मनोज (23 वर्ष) ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। तीसरे घायल योगेश का बरेली के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उनके पैर और सीने में गंभीर चोटें आई हैं। त्योहार की खुशियां मातम में बदलीं दीपक दो भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े थे। वह दिल्ली में रहकर मजदूरी करते थे। परिवार के भरण-पोषण में पिता का हाथ बंटाते थे। भाई दूज को लेकर दीपक की इकलौती बहन काफी खुश थी, लेकिन भाई की मौत से अब उसके आंसू नहीं थम रहे। मां ममता, पिता केसरी लाल और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मनोज चार भाइयों में तीसरे नंबर के थे। उन्होंने ऑप्टिकल का कोर्स करने के बाद बरेली में प्रैक्टिस शुरू की थी। तीसरे दोस्त योगेश बीटेक करने के बाद नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उधर, दो युवकों की मौत की खबर से अमौर गांव में सन्नाटा पसर गया। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए ग्रामीण और रिश्तेदार मृतकों के घर पहुंचे और पीड़ित परिजनों को ढाढ़स बंधाया। मातम में बदली नई बाइक की खुशी: दो दोस्तों की मौत, पूजा कर लौट रहे थे मंदिर से घर; एक चूक पड़ी जिंदगी पर भारी फरीदाबाद 12 दिन में सड़क हादसों में पांच की मौत शाही क्षेत्र में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 12 दिन पहले शाही-भिटौरा रोड पर दो बाइकों की भिड़ंत में तीन लोगों की जान चली गई थी।

यूपी चुनाव के लिए सामने आया नया गठबंधन, 2027 में मिलकर लड़ेंगे ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद

अनप्लग इंडिया

लखनऊ यूपी विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन का एलान किया है। ये गठबंधन प्रदेश की 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तीसरे मोर्चे की एंट्री हो गई। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए गठबंधन किया है। बताया जा रहा है कि इसकी आधिकारिक घोषणा कल लखनऊ में की जाएगी। गठबंधन की योजना प्रदेश की 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। यूपी का चुनाव अभी तक भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और सपा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा है पर औवैसी-चंद्रशेखर के दलों के गठबंधन के एलान के बाद राज्य में नये राजनीतिक समीकरण पैदा हो सकते हैं। इस नए मोर्चे में कुछ अन्य छोटे दल भी शामिल हो सकते हैं। इसके पहले, ओवैसी ने यूपी में इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी जिस पर अखिलेश यादव ने इन्कार कर दिया था। इस गठबंधन के जरिये प्रदेश के दलितों और मुस्लिमों के 40 फीसदी वोटबैंक को एकजुट करने का प्रयास किया जा सकता है जिससे इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। ओवैसी ने चुनाव को लेकर प्रचार भी शुरू कर दिया है।



हालांकि, अभी गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसका एलान बुधवार को लखनऊ में होगा। दलित समाज पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं। वह प्रदेश में दलितों के बीच लगातार अपनी पैठ मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं, प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने का फायदा समाजवादी पार्टी भी उठाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और अन्य छोटे दलों का गठबंधन प्रदेश में नए समीकरण पैदा करने के साथ ही इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती पेश कर सकता है। हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। मुस्लिम समाज ने सपा के पक्ष में रुझान दिखाया था।

चंडीगढ़-बरौनी के बीच एक-एक फेरे के लिए विशेष ट्रेन, बरेली-मुरादाबाद में होगा ठहराव

अनप्लग इंडिया

बरेली छठ पूजा से पहले यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने बरौनी-चंडीगढ़ के बीच विशेष ट्रेन का संचालन शुरू किया है। ये ट्रेन बरेली-मुरादाबाद होकर गुजरेगी। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। छठ पूजा से पहले पूर्वांचल और बिहार रूट की ट्रेनों पर यात्रियों का लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस बीच रेलवे ने बरौनी-चंडीगढ़ के बीच एक-एक फेरे के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। पूवो र रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 04538 चंडीगढ़-बरौनी



आरक्षित विशेष गाड़ी 10 नवंबर को चंडीगढ़ से रात 10 बजे चलने के बाद अंबाला कैंट, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद होते हुए अगले दिन सुबह 7:44 बजे बरेली पहुंची। यहां से चलने के बाद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए तीसरे दिन तड़के 3:30 बजे बरौनी पहुंचेगी। 04537 बरौनी-चंडीगढ़ आरक्षित विशेष गाड़ी 12 नवंबर को बरौनी से सुबह 6:30 बजे चलने के बाद दूसरे दिन सुबह 5:10 बजे बरेली आएगी। दोपहर 1:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। लखनऊ-दिल्ली एसी सुपरफास्ट में अतिरिक्त कोच दिल्ली-लखनऊ रूट पर यात्रियों के दबाव को देखते हुए रेलवे ने लखनऊ-दिल्ली एसी सुपरफास्ट में एसी तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि 12429 लखनऊ-दिल्ली एसी सुपरफास्ट में 11 से 16 और 12430 दिल्ली-लखनऊ एसी सुपरफास्ट में 12 से 17 नवंबर तक एक-एक तृतीय श्रेणी एसी कोच लगाया जाएगा।

मोबाइल रिकवरी स्कोर में यूपी में नंबर वन, 100 दिन में 3881 फोन बरामद

अनप्लग इंडिया

वाराणसी मोबाइल रिकवरी स्कोर में वाराणसी जोन पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम पर हैं। वाराणसी जोन पुलिस ने 100 दिन में 3881 मोबाइल बरामद किए। इनकी कीमत 8.14 करोड़ है। विशेष अभियान के तहत लोगों के 3881 मोबाइल फोन वाराणसी जोन पुलिस ने 100 दिन में बरामद किए। 1 अगस्त से 7 नवंबर के बीच फोन मालिकों को सौंपा गया। इनकी अनुमानित कीमत 8 करोड़ 14 लाख रुपये है। सितंबर में मोबाइल रिकवरी स्कोर डेटा के आधार पर वाराणसी जोन उत्तर प्रदेश के सभी जोन में प्रथम स्थान पर रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन नवीन अरोरा ने बताया कि जौनपुर में 949, आजमगढ़ में 783, सोनभद्र में 436, गाजीपुर में 379, मऊ में 365, चंदौली में 285, बलिया में 244, मिजार्पुर में 224, भदोही 216 मोबाइल फोन बरामद किए गए। केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के विकसित सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई की गई। जोन के सभी नौ जनपदों की पुलिस टीमों ने कार्रवाई की। जनता के लिए पुलिस की सलाह एडीजी जोन नवीन अरोरा ने बताया की अगर किसी भी व्यक्ति का मोबाइल फोन खो जाता है या गुम हो जाता है, तो घबराएं नहीं। संचार साथी की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर तुरंत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। इसके अलावा सीएससी केंद्र, संबंधित पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस की सहायता लें। अपने मोबाइल फोन का आईएमईआई नंबर हमेशा सुरक्षित रखें, जिससे फोन की तलाश और बरामदगी में तेजी लाई जा सके।

पूर्व हेड कोच का टीम पर तंज

खिलाड़ियों की फिटनेस और अनुशासन को लेकर इमरान ने सवाल उठाए

नई दिल्ली। बांग्लादेश महिला टीम के पूर्व हेड कोच सरोवर इमरान ने टीम के फिटनेस स्तर और ट्रेनिंग कल्चर पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि खिलाड़ियों को उनके कम्फर्ट जोन से बाहर निकालने और ज्यादा अनुशासन लाने की उनकी कोशिशों की वजह से उन्हें अपनी भूमिका से अलग होना पड़ा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने एशियन गेम्स के बाद अक्टूबर में सरोवर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने दिया और बाद में उनकी जगह डेविड हेम्प को नियुक्त किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने बीसीबी से सरोवर इमरान की शिकायत की थी और उनके तरीकों पर सवाल उठाया था। सरोवर ने पहले बांग्लादेश के एशियन गेम्स से बाहर होने के बाद ड्रेसिंग रूम में अशांति की बात कही थी, जिसके बाद बोर्ड ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने पर विचार किया। प्रस्तावित कार्रवाई को आखिरकार वापस ले लिया गया, जिसमें बीसीबी ने बांग्लादेश क्रिकेट के साथ उनके लंबे जुड़ाव को ध्यान में रखा।



सरोवर ने कहा कि बोर्ड ने उन्हें जारी रखने का फैसला करने से पहले कभी उनसे सफाई नहीं मांगी। उन्होंने कहा, एशियन गेम्स और एशिया कप के बाद बीसीबी ने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। मुझे एक पत्र मिला कि मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि कोई दूसरा कोच जाएगा। बीसीबी के साथ मेरी बस इतनी ही बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कोचिंग का माहौल बहुत ज्यादा संतुलन बनाने वाला हो गया था, जिससे सुधार की बहुत कम गुंजाइश बची थी।महिला टीम में शामिल होने के बाद अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा, जहां तक मेरे गुस्से की बात है, जब मैं महिला टीम में आया, तो मैंने देखा कि गेंदबाजी कोच से लेकर स्पिन बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, ट्रेनर और फिजियो सभी बहुत शांत थे। वे महिला क्रिकेटरों की हर बात सुनते हैं और इस कम्फर्ट जोन में रहकर वे सुधार नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमारी टीम आज भी वैसी ही है जैसी पांच साल पहले थी।

मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश क्रिकेट सुधर सकता है

इमरान ने कहा, एक स्पिनर 30 गेंदें फेंकने के बाद कोच से कहती है कि वह अब और गेंदबाजी नहीं करेगी और कोच मान जाता है। एक या दो बल्लेबाज पूरे दिन बल्लेबाजी करते हैं। यह सब देखने के बाद मैंने दखल देना शुरू कर दिया। मैंने उनकी फिटनेस को लेकर भी दखल दिया। उन्होंने कहा, जब मुझे उन्हें डांटने की जरूरत थी तो मैंने वैसा ही किया और अगर आप कहते हैं कि यह गुस्सा है तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश क्रिकेट सुधर सकता है। मुझे लगा कि मैं उन्हें सुधार सकता हूं और मैंने सात से आठ टूर किए और सब कुछ सिर्फ एक या दो टूर में फेल होने की वजह से खत्म हो गया। सरोवर ने इस बात को मना कर दिया कि उनकी कोचिंग स्टाइल उनके गुस्से को कंट्रोल करने में नाकामयाबी दिखाती है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ

सेंसेक्स 772, निफ्टी 210 अंक गिरा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आया है। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 772.75 अंक उछलकर 81,879.40 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 210.40 अंक बढ़कर 25,255.05 पर बंद हुआ। आज बाजार में हर ओर तेजी रही, बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक बढ़त रही। सत्र में निफ्टी बैंक मजबूती के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी पीएसयू बैंक में और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी बढ़त दर्ज की गई। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो , निफ्टी कंजप्शन , निफ्टी एफएमसीजी , निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग , निफ्टी एनर्जी , निफ्टी और निफ्टी मेटल के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।

दूसरी ओर निफ्टी आईटी , निफ्टी रियल्टी , निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थकेयर के शेयर गिरे हैं। आज लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी देखी गई।

निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 496.55 अंक बढकर 519.10 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 304.30 अंक उछलकर मजबूती के साथ 19,489.35 पर बंद हुा था। सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, इंडिगो, ट्रेंट, टाटा स्टील, बीएसई, पावर ग्रिड, आईटीसी, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, भारती



एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर लाभ में रहे जबकि टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, एनटीपीसी, इटरनल, सम फार्मा, इन्फोसिस और टीसीएस के शेयर गिरे। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार तेजी के साथ खुले। सेंसेक्स 1,142.03 अंकों की बढ़त के साथ ही 82,248.68 पर कारोबार कर रहा था। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 293.15 अंक उछलकर 25,337.80 पर आ गया।

सोने-चांदी की कीमतों में उछाल

नई दिल्ली।

सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बुधवार को तेजी आई। इसी कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दिसंबर 2026 के वायदा अनुबंध में सोने का भाव 1,41,385 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमतों में भी तेजी आईई। यह तेजी एक दिन पहले दर्ज की गई गिरावट के विपरीत है, और बाजार में नई हलचल पैदा कर रही है। आज एमसीएक्स पर, सोने के वायदा अनुबंध में 860 रुपये की जोरदार तेजी आई, जिससे इसका भाव 41,385 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इसी तरह, चांदी ने भी निवेशकों को आकर्षित किया, जहां एक किलो चांदी का भाव 3,780 रुपये बढ़कर 1,86,356 रुपये पर पहुंच गया। यह वृद्धि घरेलू बाजार में कीमती धातुओं के प्रति मजबूत रुझान को दिखाती है, खासकर वायदा कारोबार में।

दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में तेजी बरकरार है। वैश्विक स्तर पर, सोना 21.30 डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 4,051.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी भी 1.105 डॉलर की तेजी के साथ 52.33 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतें अक्सर घरेलू बाजार पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसके विपरीत राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी। मंगलवार को सोने का भाव 500 रुपये फिसलकर 1,46,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। सोमवार को 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने का भाव 1,46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस गिरावट ने बाजार में थोड़ी चिंता पैदा की थी, जबकि चांदी की कीमत लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में 1,92,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर रही थी।

नोस्कोवा ने गॉफ को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडियन वेल्स लिंडा नोस्कोवा ने डब्ल्यूटीए फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नोस्कोवा ने कोको गॉफ को 75 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 6-3 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। नोस्कोवा 2011 में पेट्रा क्वितोवा के बाद अपने पहले डब्ल्यूटीए फाइनल्स में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। डब्ल्यूटीए के आंकड़ों के अनुसार, वह 2024 में गॉफ के बाद अपने पहले दो राउंड-रॉबिन मैच जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी हैं और 2021 में एनेट कोंटावेइट के बाद ऐसा करने वाली पहली नंबर 8 सीड हैं। लिंडा नोस्कोवा ने पत्रकारों से कहा, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मैं सेमीफाइनल में हूं।



अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम में नंदिनी का चयन

चंडीगढ़ । चंडीगढ़ की तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा को दिसंबर में होने वाले भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। भारतीय टीम इस दौरे पर एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। दौरे की शुरुआत 9 दिसंबर को गेकेबरहा में होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से होगी। इसके बाद तीन वनडे मुकाबले पार्ल, केपटाउन और ब्लोमफोंटेन में खेले जाएंगे। दौरे का समापन बेनोनी और पोटचेफस्ट्रूम में होने वाली तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के साथ होगा। इस साल की शुरुआत में भी नंदिनी शर्मा ने इतिहास रचा था। वह यूटी क्रिकेट एसोसिएशन (यूटीसीए) की पहली खिलाड़ी बनी थीं, जिन्हें ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भारत की टेस्ट टीम में जगह मिली थी।



रायन बोले- न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच मजेदार होंगे

ऑकलैंड । भारत के फॉरवर्ड रायन विलियम्स न्यूजीलैंड में खेलने के अपने पिछले अनुभव का इस्तेमाल भारतीय पुरुषों के देश के पहले दौरे की तैयारी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल टीम गुरुवार को ऑकलैंड के गो मीडिया स्टेडियम में दो इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचों में से पहले मैच में ऑल व्हाइट्स का सामना करने के लिए तैयार है। यह दोनों टीमों के बीच तीसरा अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा। इससे पहले 1981 और 2018 में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं। यह दौरा भारतीय टीम के ज्यादातर सदस्यों के लिए नया है। विलियम्स ऑस्ट्रेलियाई क्लब पर्थ ग्लोरी के साथ अपने समय के दौरान न्यूजीलैंड में खेल चुके हैं। 33 साल के इस खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में पामर्स्टन नॉर्थ में वेलिंगटन फीनिक्स के खिलाफ ग्लोरी के 2-2 से ड्रॉ मैच में हिस्सा लिया था, जिसे 'डिस्टेंस डर्बी' के नाम से जाना जाता है। तस्मान में यात्रा करने की जरूरतों का अनुभव होने के कारण, वह लंबी यात्रा और समय के अंतर से आने वाली चुनौतियों को जानते हैं।



रजनीकांत की फिल्म धर्मन में हुई श्रीलीला की एंट्री



एक्ट्रेस श्रीलीला के हाथ एक और बड़ी तमिल फिल्म लगी है। वह जल्द ही रजनीकांत की फिल्म 'धर्मन' में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन अश्वथ मरिमुथु कर रहे हैं, जो 'ओह माय कडवुले' और 'ड्रैगन' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। कमल हासन के प्रोडक्शन हाउस राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने श्रीलीला के फिल्म से जुड़ने का ऐलान किया। इसके साथ ही वह पहली बार रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। प्रोडक्शन हाउस ने एक्ट्रेस का स्वागत करते हुए एक वीडियो शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'उनमें चमक है, उनमें पटाखा वाली बात है। 'धर्मन' में खूबसूरत श्रीलीला का स्वागत है।' बता दें कि फिल्म में रजनीकांत और श्रीलीला के अलावा सिमरन, नयनतारा, योगी बाबू और राशि खन्ना भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। 'धर्मन' पहली फिल्म है, जिसमें अश्वथ मरिमुथु रजनीकांत को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में डॉक्टर के किरदार में दिखेंगे रजनीकांत फिल्म के पहले पोस्टर के मुताबिक, रजनीकांत इसमें एक डॉक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। मेकर्स ने उनके किरदार को 'केट्टा पायन' यानी बुरा लड़का बताया है। यह नाम उनकी 1978 में आई फिल्म 'मुल्लुम मलारुम' के मशहूर किरदार की याद दिलाता है। अब तक सामने आए कुछ पोस्टर्स में रजनीकांत के हाथों पर खून नजर आ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म में उनका किरदार ग्रे शेड्स वाला हो सकता है। फिल्म की शूटिंग का तीसरा शेड्यूल सितंबर में पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब फिल्म की मुख्य शूटिंग अपने आखिरी चरण में पहुंच रही है। श्रीलीला और नयनतारा फिल्म की कास्ट में हाल ही में शामिल हुई हैं।



तमिल सिनेमा में लगातार बढ़ रहा है श्रीलीला का काम

श्रीलीला ने इसी साल फिल्म 'पराशक्ति' से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था। इस फिल्म में वह शिवकार्तिकेयन, रवि मोहन और अथर्वा के साथ नजर आई थीं। इसके बाद से उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें धनुष और ममूटी की फिल्म 'ओम' भी शामिल है। इस फिल्म में वह रोजा का किरदार निभा रही हैं, जो धनुष की पत्नी है। इसके अलावा वह अजित कुमार की फिल्म 'डेयरडेविल' में भी नजर आएंगी। अब 'धर्मन' के जरिए श्रीलीला को तमिल सिनेमा के एक और बड़े सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने का मौका मिला है। इस फिल्म का निर्माण रजनीकांत और कमल हासन के प्रोडक्शन हाउस राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के साथ आर महेंद्रन की टर्मरिक मीडिया मिलकर कर रहे हैं।

आईपीएल में बड़ा बदलाव... हार्दिक पंजाब किंग्स में गए, अर्शदीप मुंबई इंडियंस से जुड़े



मेरे कप्तान श्रेयस! मैं आपके पीछे खड़ा हूं

पंजाब से जुड़ने के बाद हार्दिक पंड्या का पहला बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल 2027 के लिए पंजाब किंग्स का हिस्सा बनने के बाद हार्दिक पंड्या का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि श्रेयस अय्यर उनके कप्तान हैं। रिकी पोंटिंग उनके कोच है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि वह अपने कोच और कप्तान के साथ खड़े हैं। हार्दिक इससे पहले मुंबई के कप्तान थे और अब पंजाब के साथ जुड़े हैं। उन्हें पंजाब की कप्तानी मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वह श्रेयस की कप्तानी में खेलने के लिए तैयार हैं।

श्रेयस की कप्तानी में खेलने से हार्दिक को टीम इंडिया में भी उनके साथ खेलने में आसानी होगी, क्योंकि भारतीय टी20 टीम की कमान भी श्रेयस के हाथों में ही है। हार्दिक जब भी फिट होंगे, वह भारतीय टी20 टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि अब तक कोई भी खिलाड़ी खुद को उनकी जगह पर स्थापित नहीं कर पाया है।

पंजाब में बढ़ी हार्दिक की सैलरी

हार्दिक पंड्या भले ही मुंबई इंडियंस के कप्तान थे, लेकिन उनकी सैलरी 16.5 करोड़ रुपये ही थी। वहीं, पंजाब किंग्स में उन्हें 18 करोड़ रुपये मिलेंगे। ऐसे में उन्हें सीधे 1.5 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। हालांकि, वह पंजाब की टीम के कप्तान नहीं होंगे। श्रेयस के साथ खेलने से उनके लिए टीम इंडिया में वापसी की राह भी आसान होगी, क्योंकि कप्तान के साथ ही उनका बॉन्ड अच्छा बनेगा।

हार्दिक ने ये लिखा...

हार्दिक पंड्या ने पंजाब किंग्स की जर्सी में अपनी फोटो शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, 'सत श्री अकाल, पंजाब। मेरे कैप्टन श्रेयस। मेरे कोच रिकी। मेरी टीम पूरा पंजाब। मैं आपके पीछे खड़ा हूं।' इसके साथ ही हार्दिक ने पंजाब के लिए हार्ट का इमोजी भी शेयर किया। इससे साफ है कि वह पंजाबी रंग में रंग चुके हैं और अगले सीजन में वह इस टीम को ट्रॉफी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।



डंडे उड़ा देंगे! मुंबई के लिए अर्शदीप लाएंगे तबाही

आईपीएल चैम्पियन मुंबई इंडियंस के ग्रैंड वेलकम ने मचाया गदर

पेस अटैक हुआ और खतरनाक

मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अर्शदीप सिंह का एक पावरफुल वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, हम डंडे उड़ा देंगे! फ्रेंचाइजी ने साफ कर दिया है कि बाएं हाथ का यह खतरनाक भारतीय पेसर अब वानखेड़े स्टेडियम में बल्लेबाजों की गिल्लियां उखाड़ने के लिए तैयार है। आईपीएल अर्शदीप की एंट्री से मुंबई का पेस अटैक अब बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा है।

पंड्या को मिला मुंबई का ट्रिब्यूट

दूसरी तरफ हार्दिक पंड्या की मुंबई इंडियंस से विदाई हो गई है। मुंबई ने हार्दिक के लिए एक इमोशनल वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उतार-चढ़ाव और इस बीच की हर चीज के लिए, मुंबई इंडियंस की कहानी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया हार्दिक। हार्दिक ने मुंबई के साथ 2015 में अपना सफर शुरू किया था और 2015, 2017, 2019 और 2020 के खिताब जीतने में अहम योगदान दिया था।

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी स्वैप डील पर अब आधिकारिक मुहर लग चुकी है। पांच बार की आईपीएल चैम्पियन मुंबई इंडियंस ने स्टार भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपनी पलटन में शामिल कर लिया है। 18 करोड़ रुपये की फीस पर मुंबई आए अर्शदीप का फ्रेंचाइजी ने बेहद ही अनोखे और धमाकेदार अंदाज में स्वागत किया है। मुंबई की टीम ने अर्शदीप को लेकर एक बेहद ही प्यारा और जोश से भरा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दूसरी ओर मुंबई के पूर्व कप्तान हार्दिक पंड्या अब 18 करोड़ रुपये में पंजाब किंग्स की जर्सी पहनते नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस ने जहां अर्शदीप की एंट्री पर तूफानी वीडियो शेयर किया। वहीं हार्दिक पंड्या के लिए एक खास ट्रिब्यूट वीडियो के साथ उन्हें भावुक विदाई दी।

संक्षिप्त समाचार

तुर्किये की स्टील फैक्ट्री में धमाका, 17 मजदूरों की मौत: 12 घायल

अंकारा, एजेंसी। तुर्किये के इजमिर शहर के पास सोमवार को एक स्टील फैक्ट्री में धमाका हुआ। इसमें 17 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हैं। हादसे के समय फैक्ट्री में काम चल रहा था। बीबीसीके मुताबिक, बॉयलर ले जा रही एक क्रेन गैस लाइन से टकरा गई। इसके बाद सामान नीचे लगी भट्टी में गिरा और जोरदार विस्फोट हो गया। मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय गवर्नर सुलेमान एल्बान ने बताया कि हादसा दोपहर के आसपास हुआ। उस समय क्रेन से एक नया बॉयलर ले जाया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। फैक्ट्री चलाने वाली कंपनी ने बयान जारी कर बताया कि हादसा प्लांट की एक इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी में तय रखरखाव के काम के दौरान हुआ। यह फैक्ट्री हबास डेमिर सेलिक कंपनी की है, जो तुर्किये की बड़ी स्टील कंपनियों में शामिल है। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद हादसे में हुई मौतों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और बचाव दल लगातार राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। तुर्किये में काम के दौरान होने वाले हादसे लंबे समय से चिंता का विषय बने हुए हैं। स्वतंत्र सामाजिक संगठन तुर्किश हेल्थ एंड सेफ्टी लेबर वॉच ने भी इसे देश की एक बड़ी समस्या बताया है। जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ, वह इजमिर के अलियागा इलाके में है। यह इलाका बड़े बंदरगाह के लिए जाना जाता है। यहां पुराने जहाजों को काटकर कबाड़ में बदलने का काम भी होता है।

मुश्किलों में जेन्सेन हुआंग: एक दिन में 69.5 हजार करोड़ रुपये घटी दौलत

वॉशिंगटन , एजेंसी। एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग की संपत्ति में एक ही दिन में 7.4 अरब डॉलर (69.5 हजार करोड़ रुपये) की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में दबाव के बीच उनकी कुल संपत्ति घटकर 154.7 अरब डॉलर (14.53 लाख करोड़ रुपये) रह गई। इसके साथ ही वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आठवें स्थान से फिसलकर दसवें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस गिरावट के पीछे कंपनी के सीईओ की निजी जिंदगी से जुड़ा विवाद भी चर्चा में है। हुआंग ने अपनी पत्नी लोरी हुआंग के प्रति बेवफाई की बात स्वीकार की है। हाल ही में एक कारोबारी अधिकारी के साथ उनके संबंधों को लेकर खबरें सामने आई थीं। बताया गया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि वह अधिकारी चीन के लिए सूचनाएं जुटा रही थी। फोर्ब्स के मुताबिक, नौ नवंबर को कारोबार शुरू होने के शुरुआती आधे घंटे में ही हुआंग की संपत्ति 7.4 अरब डॉलर घटकर 154.7 अरब डॉलर रह गई। इसके बाद वह बर्कशायर हैथवे के प्रमुख वॉरेन बफेट और ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन से भी नीचे आ गए। इससे पहले छह नवंबर को ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स ने हुआंग की संपत्ति 150.9 अरब डॉलर बताई थी। व्यापक तकनीकी शेयरों में बिकवाली के दौरान उनकी संपत्ति में 15.1 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई थी। एनवीडिया ने हुआंग के साथ कथित विदेशी खुफिया गतिविधि से जुड़े मामले की खबरों के बाद स्वतंत्र जांच कराने की घोषणा की है। हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में अपनी पत्नी और बच्चों को दुख पहुंचाने के लिए माफी मांगी और जांच में सहयोग करने की बात कही। हालांकि, एनवीडिया के बोर्ड ने कहा है कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कंपनी की गोपनीय जानकारी या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं से समझौता हुआ है। हुआंग फिलहाल कंपनी के प्रमुख बने हुए हैं। एनवीडिया में 3.5 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी हुआंग के पास एनवीडिया की 3.5 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी है। वह कंपनी के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा वेतन के बजाय कंपनी में उनकी हिस्सेदारी के मूल्य से जुड़ा है। यही वजह है कि एनवीडिया के शेयरों में उतार-चढ़ाव का असर उनकी कुल संपत्ति पर तेजी से पड़ता है। शेयरों की कीमत बढ़ने पर उनकी संपत्ति में फिर इजाफा हो सकता है, जबकि गिरावट जारी रहने पर उन्हें और नुकसान उठाना पड़ सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जेन्सेन हुआंग के खिलाफ प्रस्तावित क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी और हुआंग ने शेयरधारकों को गुमराह किया।

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद भी पटाखों का शोर जारी, एक्यूआई 1000 के पार

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया त्योहार के नाम पर नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती



नई दिल्ली , एजेंसी। दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद भी पटाखे चलाने का शोर जारी है, जिससे एक्यूआई कई इलाकों में 1000 से ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में पटाखे जलाने की तय समय-सीमा अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अब पटाखे पूरी तरह बैन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में केवल 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी, जिसे धार्मिक प्रथा बताया गया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और किसी भी साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर तब भी पूर्ण प्रतिबंध था। अब हवा जहरीली होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ देर रात तक और सुबह-सुबह भी पटाखों के फूटने की आवाजें आ रही हैं। इससे उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, जिन्हें सुबह जल्दी काम पर जाना होता है। बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों के लिए यह शोर और भी मुश्किल पैदा कर सकता है। सामान्य नियम के मुताबिक, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि त्योहार के नाम पर इन नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

अगर आपके आसपास रात 10 बजे के बाद भी तेज आवाज वाले पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। इसके लिए 112 नंबर पर कॉल करें। आप अपनी परेशानी बताएं और उस जगह का पूरा पता दें जहां आतिशबाजी हो रही है। इसके अलावा आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करके सूचना दे सकते हैं या वहां जाकर लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कई शहरों में जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी एजेंसियां भी विशेष हेल्पलाइन या कंट्रोल रूम चलाती हैं। यदि पड़ोसियों से विवाद का डर हो, तो पुलिस को यह बात बताकर अपनी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

एयर इंडिया की फ्लाइट हाईजैक की धमकी से कोलकाता एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

- –विमान के वॉशरूम में मिला धमकी भरा नोट, सुबह 11:10 बजे हाईजैक करने की लिखी थी बात; सभी यात्री सुरक्षित

कोलकाता , एजेंसी। कोलकाता से मुंबई जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बुधवार को हाईजैक की धमकी मिलने से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हड़कंप मच गया। विमान के वॉशरूम में धमकी भरा नोट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। एहतियात के तौर पर विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान के वॉशरूम में मिले नोट में कथित तौर पर लिखा था कि सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर विमान का अपहरण कर लिया जाएगा। उड़ान भरने से पहले ही पायलट ने इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को दे दी। इसके बाद विमान को सामान्य संचालन से अलग कर आइसोलेशन बे में पहुंचाया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर विमान की गहन तलाशी शुरू की गई। अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दी है।



अक्टूबर में भी मिला था हाईजैक अलर्ट– एयर इंडिया के विमान को धमकी मिलने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले अक्टूबर में फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 2030 को भी हाईजैक अलर्ट के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया था। बोइंग 787-9 विमान में उस समय 293 यात्री और चालक दल के 13 सदस्य सवार थे।

सीजेपी नेता दीपके को मिली राहत, व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट

नई दिल्ली , एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके को एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। उन्हें एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने चल रही जांच के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी गई है। यह मामला 16 अक्टूबर को हुए एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। दीपके मंगलवार को मंदिर मार्ग थाने में पेश नहीं हुए। उनके वकील अभिक चिमनी ने बताया कि खराब स्वास्थ्य के कारण वह व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सके, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें यह छूट प्रदान की। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान दीपके के वकील को पुलिस की रिपोर्ट और कानूनी दस्तावेजों की प्रतियां दी गई थीं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने दीपके को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनसे शांति बनाए रखने के लिए एक बॉन्ड भरने को कहा गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ हफ्ते पहले ही दीपके को एक मजिस्ट्रेट द्वारा सशर्त जमानत दी गई थी। उन्हें यह जमानत तब मिली थी जब उन पर पहले भरे गए शांति बॉन्ड का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। इस जमानत की एक मुख्य शर्त यह थी कि उन्हें एक साल तक शांति बनाए रखनी होगी और ऐसा कोई काम नहीं करना होगा जिससे शांति भंग हो। अभिजीत दीपके को 16 अक्टूबर को उस समय हिरासत में लिया गया था जब वे लहरा दो तिरंगा अभियान के दौरान मार्च में शामिल होने के लिए कनॉट प्लेस जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें इस मार्च में शामिल नहीं होने का नोटिस दिया था, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का हवाला दिया गया था। शांति बॉन्ड का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें 17 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। सूत्रों का कहना है कि दीपके अगली निर्धारित तारीख पर पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं।



फोटो खिंचाने में आगे रहने वाले चढ़ावा चोरी पर चुप क्यों?

जयराम ने श्रीराम मंदिर ट्रस्ट, निर्माण और चढ़ावे की व्यवस्था से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की मांग की



नई दिल्ली , एजेंसी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मंदिर से जुड़ी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट के गठन से लेकर निर्माण, चंदे और चढ़ावे की गिनती तथा उसे बैंक में जमा कराने तक की व्यवस्था में भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग प्रभावी भूमिका में रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में चढ़ावे की कथित चोरी की जिम्मेदारी से संबंधित लोग पीछे नहीं हट सकते। कांग्रेस नेता जयराम ने दावा किया कि वर्ष 2021 में आरएसएस से जुड़े पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। उनके अनुसार, महिपाल सिंह ने कथित चोरी की जानकारी ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय और गोपाल राव को दी थी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही हटा दिया गया। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि यदि शिकायत पहले ही सामने आ गई थी तो अब तक जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच क्यों नहीं हुई। उन्होंने मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर दीनानाथ वर्मा के कथित आरोपों का भी उल्लेख किया। वर्मा ने ट्रस्ट कार्यालय के काम में 40 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने का आरोप लगाया था। रमेश ने सवाल किया कि इस मामले में चंपत राय से पूछताछ हुई या नहीं और जिन लोगों पर आरोप लगे, उनमें से कुछ को आरोपी के बजाय गवाह क्यों बनाया गया।

कांग्रेस नेता ने चढ़ावे की गिनती से जुड़े कर्मचारियों और अन्य आरोपियों के कथित राजनीतिक-संगठनात्मक संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच केवल गिरफ्तार कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसी के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि मंदिर के निर्माण, संचालन और चढ़ावे की पूरी व्यवस्था से जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। साथ ही मंदिर के वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और दोषी पाए जाने वालों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की गई है। रमेश ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कथित चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि राम मंदिर के नाम पर मिले दान और चढ़ावे का पूरा हिसाब देश के सामने आना चाहिए।

सीएम योगी का विरोधियों पर तंज....पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कारनामों से प्रदूषित किया, उनका क्या

लखनऊ,एजेंसी। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर आतिशबाजी के कारण होने वाले प्रदूषण पर उठ रहे सवालों पर कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने साफ कहा कि दीपावली का प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कारनामों से प्रदूषित किया, उन्हें कोई नहीं पूछता। मुख्यमंत्री राजस्व विभाग के चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को 215 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरण समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब लोग पर्व और त्यौहार मनाते हैं, तभी कुछ लोगों को प्रदूषण दिखने लगता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जनता एक दिन आतिशबाजी कर ले प्रदूषण हो गया, जबकि जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट आचरण से पूरे तंत्र को दूषित किया, उनका क्या? उन्होंने कहा, प्रदूषण हुआ है, तब समाप्त भी हो जाएगा, यह कोई समस्या नहीं है। सीएम योगी ने देखकर संतोष व्यक्त किया कि लोगों ने धूम-धड़ाके के साथ दीपावली मनाई, क्योंकि उनकी सरकार ने इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने खुद अयोध्या में आतिशबाजी में शामिल होने की बात कही। इस मौके पर सीएम योगी ने पिछली सरकारों, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकाल में भर्ती आयोगों और बोर्डों में भाई-भतीजावाद हावी था, जिससे युवाओं को उनका हक नहीं मिलता था। उन्होंने याद दिलाया कि सपा सरकार ने दंगाइयों का काल मानी जाने वाली यूपीपीएसी की 34 कंपनियों को खत्म किया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके चार कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 1500 से अधिक दंगे हुए और महीनों-महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। उन्होंने मौजूदा धनतेरस पर बाजारों में शांतिपूर्ण चहल-पहल की तुलना पिछली स्थिति से की।

ट्रंप ने हेगसेथ का किया बचाव, कहा- ईरान और वेनेजुएला में जीते दो युद्ध, अब महाभियोग की बात क्यों?

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ का आलोचना और महाभियोग की बातों के खिलाफ बचाव किया। उन्होंने ईरान और वेनेजुएला में सैन्य जीत का दावा किया, साथ ही यह भी माना कि ऊर्जा की कीमतों को लेकर चिंता उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। व्हाइट हाउस में एक अचानक बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने हेगसेथ को अभियानों का निर्देशन करने का श्रेय दिया और तर्क दिया कि उन्हें उन अभियानों पर कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहिए, जिन्हें राष्ट्रपति ने सफल बताया। ट्रंप ने कहा, 'मैं यह कहता हूं, पीट हेगसेथ ने दो युद्ध जीते, और अब लोग कह रहे हैं कि चलो उन पर महाभियोग लगाते हैं।' ट्रंप ने वेनेजुएला ऑपरेशन को 48 मिनट तक चलने वाला बताया और दावा किया कि इसमें कोई मारा नहीं गया। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को वहां से बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति मिल रही है और वहां अपनी भागीदारी से पैसा कमा रहा है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि हेगसेथ ने युद्ध जीत लिया है, फिर बाद में कहा कि अभियान अभी भी जीत की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान एक समझौता चाहता है और दावा किया कि उसकी नौसेना और वायु सेना नष्ट हो गई है। उन्होंने किसी समझौते के लिए प्रस्तावित शर्तें नहीं बताईं और न ही बातचीत के लिए कोई समय-सीमा दी। उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने को अभियान का मुख्य लाभ बताया। लेकिन उन्होंने माना कि मतदाताओं की ऊर्जा की कीमतों को लेकर चिंता राजनीतिक कीमत वसूल सकती है। ट्रंप ने कहा, 'अब, अल्पावधि में, शायद मेरे लिए बुरा है क्योंकि लोग थोड़ी कम ऊर्जा लागत चाहते हैं। हम इसे वापस नीचे ले आएंगे।' ट्रंप ने यह नहीं बताया कि कीमतें कब गिरेंगी या उनकी सरकार उन्हें नीचे लाने के लिए क्या कदम उठाएगी। हेगसेथ का उनका बचाव काफी हद तक पहले के अमेरिकी युद्धों से तुलना पर आधारित था। उन्होंने वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक में परिणामों की आलोचना की और तर्क दिया कि उन संघर्षों में बिना कोई सार्थक लाभ हासिल किए भारी नुकसान हुआ था। ट्रंप ने यह भी सवाल उठाया कि पिछली सैन्य विफलताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेही की समान मांगों का सामना क्यों नहीं करना पड़ा। उन्होंने बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी का जिक्र किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे गायब हो गए थे।

ईयू रिपोर्ट- फ्रांस प्रदर्शनों में रूस-इजराइल-अमेरिका का दखल

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस में महंगाई और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट और वीडियो फैलाए गए। यूरोपीय संघ की एक आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक, रूस से जुड़े नेटवर्क ने प्रवासियों के खिलाफ नफरत फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका के 'मागा' (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) आंदोलन से जुड़े अकाउंट्स ने भी प्रदर्शन से जुड़ी गलत जानकारियां फैलाईं।

इनका मकसद फ्रांस सरकार को कमजोर दिखाना था। हालांकि, इन नेटवर्क ने प्रदर्शन शुरू नहीं कराए, बल्कि पहले से चल रहे विरोध का फायदा उठाया। देश में आतंकी हमले होने के झूठे दावे फैलाए रूस से जुड़े नेटवर्क ने सोशल मीडिया पर कई झूठे दावे फैलाए। इनमें कहा गया कि प्रवासी प्रदर्शनकारियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और देश में आतंकी हमले हो सकते हैं। इन पोस्ट के जरिए लोगों में डर और प्रवासियों के खिलाफ गुस्सा पैदा करने की कोशिश की गई। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 16 से 18 अक्टूबर के बीच रूस समर्थक समूहों के सबसे ज्यादा देखे गए 10 पोस्ट को 28 लाख बार देखा गया।

इसी दौरान अमेरिका के 'मागा' आंदोलन से जुड़े लोगों के 10 सबसे ज्यादा देखे गए पोस्ट को 4.9 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। वहीं, इजराइली अधिकारियों, सरकारी अकाउंट्स और प्रभावशाली लोगों के ऐसे ही 10 पोस्ट को 3.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया।

मागा यानी 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' अमेरिका का दक्षिणपंथी आंदोलन है, जो राष्ट्रपति ट्रम्प और उनकी राजनीति का समर्थन करता है।

फ्रांस के पीएम ने श्रमिक संगठनों के साथ बैठक की फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच सोमवार को



उद्योग संगठनों और श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ाने और वेतन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। सरकार न्यूनतम वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। इसका मकसद महंगाई से परेशान लोगों को राहत देना है। फ्रांस से शुरू हुए प्रदर्शन 31 देशों तक पहुंचे दुनिया भर में हिंसा और विरोध प्रदर्शनों पर नजर रखने वाली संस्था एक्लेड के आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच यूरोप के 31 देशों में महंगाई और शिक्षा व्यवस्था को लेकर 1700 से ज्यादा प्रदर्शन हुए। इनकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी। फ्रांस में महंगाई और शिक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा। इसके बाद यह विरोध स्पेन और इटली जैसे देशों में भी फैल गया। यहां हजारों लोगों ने महंगे घरों और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। यानी लोगों की आर्थिक परेशानियां अब कई देशों में सरकारों के लिए चुनौती बन रही हैं। स्पेन समेत 5 देशों में और तेज हो सकते हैं प्रदर्शन यूरोप के कई देशों में आने वाले दिनों में विरोध बढ़ने के आसार हैं। स्पेन में ट्रेड यूनियनों ने 11 नवंबर को हड़ताल रखी है। वहीं, इटली के सबसे बड़े श्रमिक संगठन ने महंगाई के खिलाफ 20 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इसके अलावा जर्मनी, पुर्तगाल और अल्बानिया में भी प्रदर्शन तेज हो सकते हैं।

अमेरिका को मजबूत औद्योगिक आधार की जरूरत, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हो: जेडी वेंस

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने आपूर्ति से जुड़े जोखिमों को बढ़ाया था। साथ ही, उन्होंने पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले अमेरिकी व्यवसायों के लिए अधिक फंडिंग देने का वादा किया। 'नेशनल वेटरन्स स्मॉल बिजनेस वीक' के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेडी वेंस ने छोटे उद्यमों के समर्थन को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक ऐसे औद्योगिक आधार की जरूरत है, जो उसके सैनिकों को जरूरी चीजें मुहैया करा सके और आर्थिक विकास को बनाए रख सके। वेंस ने कहा कि देश ने दशकों तक इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया कि सामान कहां बन रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवसायों और नीति-निर्माताओं ने उत्पादों को उनके बनने की जगह से अधिक जरूरी समझा।

उपराष्ट्रपति ने मेक्सिको, चीन और अपने गृहनगर मिडिलटाउन, ओहियो का उदाहरण देते हुए बताया कि इस तरीके में घरेलू उत्पादन के महत्व को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि कोविड के दौरान हम सभी ने यह सबक सीखा और सच कहूं तो, हमें यह सबक उससे बहुत पहले ही सीख लेना चाहिए था कि कभी-कभी जब आप महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं, तो जरूरत के समय वे हमेशा उपलब्ध नहीं होते।'

वेंस ने कहा कि प्रशासन इस साल पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए करोड़ों डॉलर देगा और आने वाले कुछ वर्षों में यह मदद अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। वेंस ने कहा, 'उनका मानना ??है कि केली लोफ्लर के नेतृत्व में 'स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन' के जरिए पूर्व सैनिकों से जुड़े छोटे व्यवसायों को पहले ही 1.3 अरब डॉलर दिए जा चुके हैं।' हालांकि, उन्होंने इस आंकड़े के लिए कोई समय-सीमा या विस्तृत विवरण नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि इस मदद से व्यवसायों के पास कर्मचारियों को काम पर रखने, उन्हें प्रशिक्षित करने और अपने उत्पादों का विस्तार करने के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा। वेंस ने कहा, 'आप लोग कई मायनों में अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।'

वेंस ने सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में छोटे व्यवसायों के योगदान का जिक्र किया और 'पैट्रियट मिसाइलों' में उनकी भागीदारी का उदाहरण दिया। उन्होंने यह भी बताया कि 1,200 छोटे व्यवसायों ने अमेरिकी सैनिकों के लिए 'साइडआर्म्स' विकसित करने में मदद की है।

उन्होंने तर्क दिया कि ये कंपनियां यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि सैन्य कर्मियों के पास ऐसे भरोसेमंद हथियार हों, जिन्हें उनके ही देशवासियों, जिनमें पूर्व सैनिक भी शामिल हैं, ने बनाया हो। उन्होंने कहा कि इन व्यवसायों का समर्थन करना सिर्फ नौकरियों



या आर्थिक उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं बढ़कर है।

वेंस ने पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए लोफ्लर और जेपी मॉर्गन चेस को धन्यवाद दिया। उनका परिचय देते हुए, लोफ्लर ने मरीन कॉर्प्स में उनकी सेवा और व्यावसायिक अनुभव का जिक्र किया।

इसी अनुभव का हवाला देते हुए, वेंस ने बताया कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने सिनसिनाटी में एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर के तौर पर काम किया था। उनकी फर्म ने युवा टेक्नोलॉजी कंपनियों को सपोर्ट किया, जिनमें अनुभवी लोगों के स्वामित्व वाले व्यवसाय और हथियारों की सप्लाई चेन में योगदान देने वाली कंपनियां शामिल थीं।

उन्होंने छोटे व्यवसायों के लिए दी जाने वाली सहायता में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए लोफ्लर के प्रयासों की भी तारीफ की। वेंस ने दावा किया कि महामारी के दौर में फंड जारी होने के बाद धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे असली कंपनियों का पैसा गलत हाथों में चला गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन जांच प्रक्रिया को सख्त कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसबीए लोन के लिए आवेदन करने वाले लोग इसके योग्य हैं। उन्होंने इन प्रयासों से हुई रिकवरी या बचत के बारे में कोई आंकड़े नहीं दिए।

वेंस ने व्यवसाय मालिकों और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि वे सरकारी सहायता में मौजूद कमियों की पहचान करने में मदद करें। उन्होंने कहा, 'हमें बताएं कि हम अपने समुदायों में पूर्व सैनिकों की ओर से संचालित छोटे व्यवसायों को बेहतर तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं।' इसके साथ ही, उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासन चाहता है कि कंपनियां अपना विस्तार करें, नए लोगों को काम पर रखें और नए उत्पाद विकसित करें, साथ ही देश की आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की क्षमता को भी मजबूत करें।

नेक्सटऐज मीडिया एंड कांलटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए, प्रकाशक, संपादक अनीता यादव द्वारा मुद्रक, रजनी कुमारी मेसेर्स साईं प्रिंटिंग प्रेस डी-85 सेक्टर-06 201301 से मुद्रित कराकर 962 सरफाबाद सेक्टर-73, नोएडा-201304 से प्रकाशित किया,
प्रधान संपादक : रिंकू यादव संपादक : अनीता यादव PRGI No. UPHIN/26/A8255 Ph. : 4403949, Email : unplugindia26@gmail.com